चतुर्थ अध्याय
राष्ट्रीय विकास परिषद
और
पंचर्षीय गोजनार्यों
चतुर्थ अध्याय
राष्ट्रीय विकास परिषद एवं पचवर्षीय योजनायें

राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रथम कार्य योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं पर विचार करना और उसकी स्वीकृति देना है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय विकास परिषद की कार्यवाही को इस प्रकार देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद और प्रथम पंचवर्षीय योजना
राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रथम बैठक एवं प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनिवार्य झापट - 8, 9 नवम्बर 1952 को हुआ।
इसमें तीन उद्देश्य निर्धारित किये गये।
1. योजना के विकास के लिए राष्ट्रीय संसाधनों को सशक्त एवं गतिमान करना।
2. प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक योजनाओं को प्रारंभित करना।
3. देश के प्रत्येक क्षेत्र एवं भाग में संयुक्त एवं तीव्र विकास के लिए प्रयास करना।

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किये गये:
1. संयोजन समिति पर राष्ट्रीय योजनाओं का मूल्यांकन करना।
2. उन सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं को देखना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करते हैं।
3. उन मूल्यों का अवलोकन करना जिनके द्वारा राष्ट्रीय योजनाओं के उद्देश्य एवं परिणाम हासिल किये जायें।

राष्ट्रीय विकास परिषद की द्वितीय बैठक हैदराबाद हाउस नई दिल्ली 6, 7 अक्टूबर 1953 को हुई। इस योजना के अन्तर्गत हासिल की गई उपलब्धियों:
1. शिक्षा एवं ऊर्जा
2. कृषि उत्पादन
3. सामुदायिक योजनायें
4. स्थानीय विकास के कार्यक्रम

1. Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-I (1st to 14th meetings)
   Government of India Planning Commission २०२१ संख्या—1 79
5. स्वास्थ्य कार्यक्रम

(1) सिंचाई एवं उज्ज्वलीला

इस क्षेत्र के अन्तर्गत सत्तोषजनक परियोजना हासिल हुए और तब लघु सिंचाई योजनाओं में कुछ राज्यों द्वारा अस्त्यमीजनक परियोजना दिये गये।

(2) कृषि उपत्यका

जूत तथा तिलहन के उपत्यकाएं में घोड़े और अधिक प्राप्त प्राप्त उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया गया।

(3) सामुदायिक प्रोजेक्ट

इस क्षेत्र में निम्नप्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता थी:

(क) कृषि उपत्यका का बढ़ाना पर जोर देना।

(ख) सहकारी संस्थाओं के गठन एवं वृद्धि करण पर जोर।

(ग) लघु एवं कृषि उद्योग

(घ) स्वास्थ्य विकास के कार्यक्रम - सत्तोषजनक परियोजना हासिल हुए राज्य सरकारों से अनुशंसा किया गया कि वह अपने कार्यक्रमों में स्वास्थ्य संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इन प्रारंभों के तौर पर प्रयोजन द्वारा उपलब्ध कराये गये धन का प्रयोग करें।

(ङ) स्वास्थ्य कार्यक्रम - प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता करना तथा इन कार्यक्रमों में सामुदायिक ईकाइयों की मदद लेना।

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956

भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई। इस योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। यद्यपि यह योजना 1951 से शुरू हो चुकी थी, परन्तु इसे अनिष्ठ रूप से 1952 तक तय किया जा सका। योजना के निर्माण के समय देश के सामने कई समस्यायें लगी जोकि वास्तव में बहुत समय से चली आ रही थीं परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने अधिक भावनाक रूप धारण कर लिया था। कल्याणकारी
राष्ट्रीय स्थापना, जो कि भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य था, की पूर्ति के लिए भी इन समस्याओं का समाधान करना जरूरी समझा गया। प्रथम योजना में 2378 करोड़ व्यय करने का निश्चय किया गया, लेकिन वास्तविक व्यय 1960 करोड़ ही हो सका।

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) युद्ध एवं देश विभाजन से उपन्यास आर्थिक असमानताओं को दूर करना।
(ii) प्रथम योजना से पूर्व की योजनाओं को लक्ष्यों को पूरा करना।
(iii) एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य-सहन का स्तर उच्चतर बनाया जा सके।

योजना में निम्नलिखित प्राथमिकताओं का क्रम इस प्रकार था:

(i) इस योजना में कृषि को सर्वप्रथम महत्व दिया गया। कृषि के स्थायी विकास के लिए आर्थिक उपकरण, उन्नतीशील श्रेणी, राजनीतिक खाद और शिक्षा की सुविधाओं का विकास करना योजना का मुख्य उद्देश्य था।
(ii) कृषि के बाद दूसरा स्थायी विभिन्न अर्थत शक्ति के उत्पादन को दिया गया।
(iii) ग्रामीण श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के लिए सामुदायिक विकास योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए साइंस के निर्माण पर विशेष बल दिया गया।
(iv) इसके अलावा समाज कल्याण के क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विकिटना उत्पादक स्वस्थ आदि के विकास को महत्व प्रदान किया गया ताकि मानवीय कल्याण और मानवीय पूर्ण निर्माण में वृद्धि हो सके।

राष्ट्रीय विकास परिषद और द्वितीय पंचवर्षीय योजना

20-21 जनवरी 1956 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सम्पन्न हुई। कृष्ण महत्त्वपूर्ण विषय जो राष्ट्रीय विकास परिषद के संज्ञान में आये तथा जो राष्ट्र के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण थे।

(i) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए खाका तैयार किया गया,
(ii) निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में विकास के लिए पूर्ण निवेश।

81. शिं, एस.पी., "आर्थिक विकास एवं नियोजन" एसिएसबीए एड़, कॉन्सेप्ट्स, पृष्ठ 178-179.
(iii) क्षेत्रीय विकास के लिए कार्यक्रम।
(iv) रोजगार के अवसरों के क्षेत्रीय विविधता के लिए योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम
(v) शिक्षित बेरोजगारी
(vi) इन्जीनियरों की आवश्यकता

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक 3 मई 1958 को सम्पन्न हुई। ज्ञान आउटले रु 2456 करोड़ प्रथम तीन वर्षों के लिये

(i) Balance From revenues 439 Crores
(ii) Railways Contribution 129 Crores
(iii) Loan from the Public, small savings and other Capetal Receipts 533 Crores
(iv) External assistance 438 Crores
(v) Deficit Financing 917 Crores

Total 2456 Crores

Orginal and Revised Allocations

<table>
<thead>
<tr>
<th>Centere</th>
<th>Orginial States including union Territories</th>
<th>Total</th>
<th>Percent of Total</th>
<th>Centre</th>
<th>Revised States including Union Territories</th>
<th>Total</th>
<th>Percent of Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Agriculture and Community Development</td>
<td>65</td>
<td>503</td>
<td>568</td>
<td>65</td>
<td>503</td>
<td>568</td>
<td>11.80</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Irrigation and Power</td>
<td>105</td>
<td>808</td>
<td>913</td>
<td>72</td>
<td>788</td>
<td>860</td>
<td>17.90</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Village &amp; Small Industries</td>
<td>80</td>
<td>120</td>
<td>200</td>
<td>60</td>
<td>140</td>
<td>200</td>
<td>4.20</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Industries &amp; Minerals</td>
<td>667</td>
<td>23</td>
<td>690</td>
<td>857</td>
<td>23</td>
<td>880</td>
<td>18.40</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Transport and communications</td>
<td>1203</td>
<td>182</td>
<td>1385</td>
<td>1175</td>
<td>164</td>
<td>1345</td>
<td>28.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Social Services</td>
<td>394</td>
<td>549</td>
<td>943</td>
<td>321</td>
<td>542</td>
<td>863</td>
<td>18.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Miscellaneous</td>
<td>43</td>
<td>56</td>
<td>99</td>
<td>37</td>
<td>47</td>
<td>84</td>
<td>1.70</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>2557</strong></td>
<td><strong>2241</strong></td>
<td><strong>4798</strong></td>
<td><strong>2587</strong></td>
<td></td>
<td><strong>2207</strong></td>
<td><strong>4800</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-I (1st to 14th meetings)
   Government of India Planning Commission पृष्ठ संख्या—121.
7. वहीं पृष्ठ संख्या—268
8. वहीं पृष्ठ संख्या—270

82
Outlook on Resources (Rs. Crores)

Likely actual for the first 3 years of the plan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1956-57</th>
<th>1957-58</th>
<th>1958-59</th>
<th>Total for 3 years</th>
<th>Estimates for the last two years 1959-60 and 1960-61</th>
<th>Total 1956-61</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Domestic Budgetary Resources</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a. Balance from current Revenue</td>
<td>139</td>
<td>150</td>
<td>150</td>
<td>439</td>
<td>320</td>
<td>759</td>
</tr>
<tr>
<td>b. Railways Contribution</td>
<td>34</td>
<td>45</td>
<td>50</td>
<td>129</td>
<td>121</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>c. Loans and small Savings</td>
<td>200</td>
<td>127</td>
<td>217</td>
<td>544</td>
<td>440</td>
<td>984</td>
</tr>
<tr>
<td>d. unfunded debts Miscellaneous Capital Recept</td>
<td>-14</td>
<td>-25</td>
<td>28</td>
<td>-11</td>
<td>40</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>359</td>
<td>297</td>
<td>445</td>
<td>1101</td>
<td>921</td>
<td>2022</td>
</tr>
<tr>
<td>2. External Assistance</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Deficit Financing</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. Total Resources outlay</td>
<td>635</td>
<td>861</td>
<td>960</td>
<td>2456</td>
<td>1804</td>
<td>4260</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Allocations and outlays by the major heads of development

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Allocations as originally made in the Plan</th>
<th>Percent of Total</th>
<th>Revised allocations to accommodate the higher cost of some projects with in the ceiling of Rs. 4800 crores</th>
<th>Percent of Total</th>
<th>Outlays now proposed to correspond with the resources position</th>
<th>Percent of Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Agriculture &amp; Community Development</td>
<td>568</td>
<td>11.80</td>
<td>568</td>
<td>11.8</td>
<td>510</td>
<td>11.30</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Irrigation &amp; Power</td>
<td>913</td>
<td>19.00</td>
<td>860</td>
<td>17.9</td>
<td>820</td>
<td>18.20</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Village &amp; Small Industries</td>
<td>200</td>
<td>4.20</td>
<td>200</td>
<td>4.2</td>
<td>160</td>
<td>3.60</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Industries &amp; Mineral</td>
<td>690</td>
<td>14.40</td>
<td>880</td>
<td>18.4</td>
<td>790</td>
<td>17.50</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Transport &amp; Communication</td>
<td>1385</td>
<td>28.90</td>
<td>1345</td>
<td>28</td>
<td>1340</td>
<td>29.80</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Social Services</td>
<td>945</td>
<td>19.70</td>
<td>863</td>
<td>18</td>
<td>810</td>
<td>18.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Miscellaneous</td>
<td>99</td>
<td>2.00</td>
<td>84</td>
<td>1.7</td>
<td>70</td>
<td>1.60</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>4800</strong></td>
<td><strong>100.00</strong></td>
<td><strong>4800</strong></td>
<td><strong>100</strong></td>
<td><strong>4500</strong></td>
<td><strong>100.00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956 से 1961)**

देश में प्रथम योजना के समाप्त होते ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू कर दी गई थी। योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 के बीच रहा। योजना की रूपरेखा प्रोफील पीपीसी महाननोविन्स द्वारा तैयार की गई जो वास्तव में उनके एक विकास मूलक पर आधारित थी। द्वितीय योजना का मुख्य लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना, तीव्र जीवनसाधन विकास एवं आर्थिक विकास को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना था।

---

10. Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-I (1st to 14th meetings) Government of India Planning Commission \पृष्ठ संख्या--272.
इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय ₹ 2472 करोड़ का हुआ जिसका 23 प्रतिशत भाग (₹ 1090 करोड़) विदेशी सहायता द्वारा पूरा किया गया।

₹ 10 वर्षों लाल नेहरू के शासन में, "हमारी द्वितीय पंचदशकीय योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत का पुन:निर्माण करना, भारत में औद्योगिक प्रगति की नीति रखना, जनता के कमजोर एवं अधिकारी अधिकारी वर्ग को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना और देश के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास करना है।"

1. योजना का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना था जिसके लिए पाँच वर्षों में 25 प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया।

2. तीसरी भारतीय प्रगति से औद्योगिक से लेकर अकेले एक भारी उद्योगों को प्रारंभिकता दी गयी।

3. देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसरों में वृद्धि करना।

4. देश में आय व समानता की विषमताओं को कम करना ताकि व्यापार व समानता को बनाये रखा जा सके।

राष्ट्रीय विकास परिषद और तीसरी पंचदशकीय योजना

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक 19, 20 मार्च 1960 को सम्पन्न हुई।

तीसरी पंचदशकीय योजना के मुख्य बिनु जो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक (3, 4) (अप्रैल 1959) को सम्पन्न हुई में रखे गये थे।

1. प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय को कम से कम 5 प्रतिशत बढ़ाना तथा पूरी निवेश की प्रतिशत वृद्धि की विकास परिषद दर में सहायता बनाना।

2. खाद्य उत्पादन में आलादी कार्य करना, उद्योग एवं निर्माण की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना।

3. आधारभूत उद्योगों को जैसे-जैसे इतिहास, ईच्छा एवं ऊर्जा महीने आदि की आवश्यकताओं को दस वर्षों में हासिल करना।

4. सेवागार अवसरों के लिये पर्याप्त संसाधन मुटाना
5. आय की अर्थमानता को कम करना तथा आर्थिक अवसरों का वितरण।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने निम्न बिंदुओं पर ज्यादा जोर दिया है:
1. पंचायतों का सशक्तीकरण, स्थानीय सिंचाई सुविधाओं का बढाना मूदा संकेत कार्यक्रम चलाना।
2. पर्यावरण मात्रा में प्रेषजल उपलब्ध करना।
3. ग्राम विद्यालयों का निर्माण।
4. प्रत्येक गाँव को नजदीकी सड़कों एवं रेलवे स्टेशनों से जोड़ना।
5. स्थानीय विकास कार्यक्रमों को बढाना जैसे कृषि उत्पादनों में प्रगति गाँवों का आपसी सामंजस्य बढाना, ज्याक रंग का विकास तथा इन सभी प्रयासों का राज्य प्रगति से जोड़ना।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक 13,14 जनवरी 1961 को सम्पन्न हुई।

States Resources for the Third Plan (Rs. In Crores)¹⁴

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Balance from Current revenues at 1960-61 rates of taxation</td>
<td>-5</td>
<td>-3</td>
<td>3</td>
<td>14</td>
<td>25</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Surpluses of Public enterprises</td>
<td>19</td>
<td>22</td>
<td>27</td>
<td>36</td>
<td>45</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Surpluses of Public enterprises</td>
<td>72</td>
<td>78</td>
<td>59</td>
<td>75</td>
<td>90</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Loans from the public (Net)</td>
<td>67</td>
<td>71</td>
<td>75</td>
<td>79</td>
<td>85</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Provident funds (net)</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Withdrawal from reserves</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Total of 1 to 7</td>
<td>125</td>
<td>143</td>
<td>143</td>
<td>190</td>
<td>205</td>
<td>806</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Additional taxation</td>
<td>40</td>
<td>115</td>
<td>135</td>
<td>150</td>
<td>170</td>
<td>610</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td>165</td>
<td>258</td>
<td>278</td>
<td>340</td>
<td>375</td>
<td><strong>1416</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

¹² Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-I (1st to 14th meetings) Government of India Planning Commission पृष्ठ संख्या—484
¹³ यही पृष्ठ संख्या—510
¹⁴ Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-II (15th — 25th meetings) Government of India Planning Commission पृष्ठ—86
## Estimates of States Resources for the Third Plan
(Comparison between the estimates as worked out earlier and as worked out now)
(Rs in Crores)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>(I) As in the Draft Outline</th>
<th>(II) As on the Basis of Discussions</th>
<th>(III) As worked out now</th>
<th>Difference Between III and I</th>
<th>Difference Between III and II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Balance from current revenues at 1960-61 rates of taxtion</td>
<td>-35</td>
<td>34</td>
<td>-12</td>
<td>23</td>
<td>-46</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Surpluses of Public enterprises</td>
<td>140</td>
<td>149</td>
<td>149</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Loans from the public (Net.)</td>
<td>330</td>
<td>374</td>
<td>350</td>
<td>20</td>
<td>-24</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Small Savings (net)</td>
<td>360</td>
<td>377</td>
<td>377</td>
<td>17</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Provident Funds (net)</td>
<td>60</td>
<td>79</td>
<td>79</td>
<td>19</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Balance of miscellaneous capital receipt over non plan disbursments</td>
<td>-205</td>
<td>-233</td>
<td>-233</td>
<td>-28</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Withdrawal from cash or reserves</td>
<td>0</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td>26</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Total of 1 to 7</td>
<td>650</td>
<td>806</td>
<td>736</td>
<td>86</td>
<td>-70</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Additional taxation</td>
<td>550</td>
<td>610</td>
<td>610</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>1200</td>
<td>1416</td>
<td>1346</td>
<td>146</td>
<td>-70</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Resources for the third Plan: Centre and States taken together

(Rs. in Crores)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Balance from current revenues at 1960-61 rates of taxation</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>66</td>
<td>104</td>
<td>145</td>
<td>384</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Railway’s Contribution</td>
<td>21</td>
<td>23</td>
<td>20</td>
<td>17</td>
<td>27</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Surpluses of Public Enterprises</td>
<td>34</td>
<td>52</td>
<td>77</td>
<td>121</td>
<td>165</td>
<td>449</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Loans from the public (Net.)</td>
<td>152</td>
<td>138</td>
<td>239</td>
<td>170</td>
<td>151</td>
<td>850</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Small Savings (net)</td>
<td>103</td>
<td>110</td>
<td>117</td>
<td>123</td>
<td>132</td>
<td>585</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Provident Funds (net)</td>
<td>46</td>
<td>47</td>
<td>50</td>
<td>52</td>
<td>54</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Steel Equalization Fund (net)</td>
<td>30</td>
<td>31</td>
<td>32</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Balance of miscellaneous capital receipt over non plan disbursments</td>
<td>25</td>
<td>38</td>
<td>44</td>
<td>51</td>
<td>50</td>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Total of 1 to 8</td>
<td>445</td>
<td>474</td>
<td>645</td>
<td>671</td>
<td>758</td>
<td>2993</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Deficit Financing</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1710</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Additional taxation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2200</td>
</tr>
<tr>
<td>12. External Assistance</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>7453</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

15. Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-II (15th – 26th meetings) Government of India Planning Commission नॉन विकास आयोग 88

88
Distribution of Outlay between the Centre and the States

(Rs. in Crores)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Draft out line</th>
<th>NDC Sep. 196</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Agriculture &amp; Community Development</td>
<td>1025</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Major and Medium Irrigation</td>
<td>650</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Power</td>
<td>925</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Village &amp; small Industries</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Industries &amp; Mineral</td>
<td>1500</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Transport &amp; Communications</td>
<td>1450</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Social Services</td>
<td>1250</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Inventories</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>7250</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

16. Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-II (15th – 25th meetings)
Government of India Planning Commission राष्ट्रीय विकास आयोग – 89
**Total Outlays States Including Union Territories**
(Rs. In Crores)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Before discussion</th>
<th>Afterdiscussion</th>
<th>Deviation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Agriculture &amp; Community Development</td>
<td>900</td>
<td>947</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Major and Medium Irrigation</td>
<td>645</td>
<td>651</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Power</td>
<td>800</td>
<td>938</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Village &amp; small Industries</td>
<td>130</td>
<td>136</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Industries &amp; Mineral</td>
<td>50</td>
<td>76</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Transport &amp; Communications</td>
<td>225</td>
<td>271</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Social Services</td>
<td>950</td>
<td>918</td>
<td>-32</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Miscellaneous</td>
<td>0</td>
<td>81</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>3700</strong></td>
<td><strong>4018</strong></td>
<td><strong>318</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

The Head ‘Miscellaneous’ includes some expenditure which should be reclassified under other heads and adjusted against them.  

---

17. Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-II (15th - 25th meetings) Government of India Planning Commission पृष्ठ संख्या—90
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961 से 1966)

तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के बीच रहा। निर्देशंद्र प्रधान दो योजनाओं की समाप्ति के साथ-साथ देश में आर्थिक नियोजन के लिए एक उपयोगक वातावरण तैयार हो चुका था। किन्तु साथ ही साथ दूसरी योजना की धीमी प्राप्ति से यह पता चल गया कि भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा कृषि उत्पादन का धीमी गति से बढ़ाना है। अतः तीसरी योजना में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए कृषि उत्पादन का विस्तार करने और कृषि पर से जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही, मूल उद्योगों जैसे इस्पात ईद्यन, संचालनशक्ति, मशीन निर्माण, रसायन पदार्थ जोंकि आर्थिक विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं पर पर्याप्त बल दिया गया। दूसरी योजना के अंत पर योजना निर्माताओं द्वारा यह अनुमान किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था “उठान अवस्था” (Take off stage) में प्रवेश कर गई है और दोनों योजनाओं के फलस्वरूप देश में एक ऐसे सर्वाधिक बीच का निर्माण हुआ है जिसमें आर्थिक विकास त्वरित हो सके। इसलिए योजना का लक्ष्य “स्वाभाविक और स्वयं स्फूर्ति अर्थ व्यवस्था” (Self Reliant and Self Generating Economy) का रखा गया।

तृतीय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:

1. राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करना और एक ऐसे निवेश बीच का निम्नाण करना कि भारतीय योजनाओं में भी इस विकास दर को बनाये रखा जा सके। योजना प्रारूप में यह स्पष्ट किया गया कि “प्रायधिक प्रतिशत आर्थिक की विकास दर प्राप्ति करने के लिए विनियोग के 11.50 प्रतिशत व्यवस्था स्तर की अपेक्षा, राष्ट्रीय आय का 14 प्रतिशत से अधिक निवेश करना अनिवार्य होगा।

2. खाद्यान्न के क्षेत्र में अत्यन्तीति प्राप्त करना और घरेलू उद्योगों तथा निर्यात की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना।

3. मूल व आयारमूर उद्योगों का इस प्रकार विकास करना कि भारतीय आयोजन की सभी आवश्कताओं को देश के आत्मनिर्भर साह्यों के द्वारा पूरा किया जा सके।

4. देश की मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करना और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ाना।
## तीसरी योजना काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रतिशत वृद्धि</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रति व्यक्ति आय (रू.)</td>
<td>309</td>
<td>308</td>
<td>318</td>
<td>335</td>
<td>310</td>
<td>316</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## तीसरी योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 100 मिटर टन अधिकतम 6 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य गया था। किन्तु खाद्यान्न उत्पादन में केवल 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ – तीसरी योजना के आधार वर्ष 1960-61 में खाद्यान्न उत्पादन 82.3 मिटर था जो 1962-63 में घटकर 78.5 मिटर रह गया। चौथा वर्ष (1964-65) खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि से एक रिकार्ड वर्ष था इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन 89 मिटर
था। किंतु 1965-66 में भर्तकर सुखेके के कारण यह पुनः घटकर 72 मिलियन रह गया। कृषि उत्पादन की अस्तित्वजनक प्रगति का मुख्य कारण भू-सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की शिक्षितता और कृषि आदानों की अल्प उपलब्धता थी।

तीसरी योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि भी अधिक सन्तोषजनक नहीं रही। कुछ हद तक इसका आशिक कारण, शीघ्र प्रतिफल देने वाले उपयोगिता वस्तु उद्योगों की अपेक्षा लम्बी अवधि वाले पूरी वस्तु उद्योगों पर अधिक बल देना था। औद्योगिक उत्पाद में 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। जबकि वास्तविक वृद्धि 5.7 प्रतिशत प्रति वर्ष रही।

यद्यपि तीसरी योजना का मूल उद्देश्य कीमतों में स्थायित्व लाकर लोगों के जीवन स्तर को बढ़ा उठाना था। किंतु यह मूल न केवल अचूक रहा बल्कि योजना काल में कीमतों अर्थात् महंगाई और भी अधिक बढ़ गई। खाद्यान्वयन के कीमत भी सूक्ष्मकर्म में 48.4 प्रतिशत दर की गई और सभी वस्तुओं की कीमत सूक्ष्मकर्म में 36.4 प्रतिशत दर की गई। फलस्वरूप इसकार्यता महंगाई के कारण लोगों का जीवन कमजोर हो गया और जीवन निर्वाह स्तर सूक्ष्मकर्म काफी घट गया। यद्यपि सरकार ने कीमत वृद्धि पर अंदूरा लगाने के लिए विवरणात्मक उपायों का सहारा लिया किन्तु जतना को इस अन्वाही महंगाई से कोई राहत न मिल सकी। कीमत वृद्धि का एक अन्य दुष्प्रभाव यह भी रहा कि 'बचत आय अनुपात' 10.5 प्रतिशत तक ही बढ़ सका।

<table>
<thead>
<tr>
<th>ग्राहक</th>
<th>खाद्यान्वयन</th>
<th>औद्योगिक माल</th>
<th>औद्योगिक माल</th>
<th>सभी वस्तुओं</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रतिशत वृद्धि</td>
<td>48.4</td>
<td>32.6</td>
<td>22.1</td>
<td>36.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

दूसरी योजना के अन्त में बेरोजगारों की संख्या 70 लाख थी। तीसरी योजना काल में श्रम शक्ति में 170 लाख की वृद्धि हुई परंतु केवल 145 लाख लोगों को बेरोजगार दिलाया जा सका। इस प्रकार तीसरी योजना के अन्त में रोजी-रोटी की तलाश में भटकने वाले बेरोजगारों की संख्या लगभग 95 लाख थी।

18. ब्रह्म, एमएलएला “विकास का अर्थसार्थ एवं आयोजन” विश्वविद्यालय प्रकाशन प्राथमिक दिल्ली-91 पुस्तक संख्या-607-608
था। किन्तु 1965-66 में बर्याकर सूखे के कारण यह पुनः घटकर 72 मिटटन रह गया।

कृषि उत्पादन की अस्तित्वजनक प्रगति का मुख्य कारण मू-सूचार कार्यक्रमों को लागू करने की शिखरता और कृषि आदानों की अलग उपलब्धता थी।

तीसरी योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि भी अधिक सत्तवाजनक नहीं रही। कुछ हद तक इसका आशिक कारण, सीधे प्रतिफल देने वाले उपयोगक्ता वस्तु उद्योगों की अपेक्षा लम्बी अवधि वाले पूंजी वस्तु उद्योगों पर अधिक बल देना था। औद्योगिक उत्पाद में 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। जबकि वास्तविक वृद्धि 5.7 प्रतिशत प्रति वर्ष रही।

यद्यपि तीसरी योजना का मूल उद्देश्य कीमतों में स्थायित्व लाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। किन्तु यह लक्ष्य न केवल अधूरा रहा बल्कि योजना काल में कीमतों अर्थात मंहगाई और भी अधिक बढ़ गई। खाद्यान्नों की कीमतें सूचकांक में 48.4 प्रतिशत दर्ज की गई और सभी वस्तुओं की कीमत सूचकांक में 36.4 प्रतिशत दर्ज की गई।

फलस्वरूप इसकमरतरों मंहगाई के कारण लोगों का जीवन कठिन हो गया और जीवन निर्वाह स्तर सूचकांक काफी घट गया। यद्यपि सरकार ने कीमत वृद्धि पर अंधुश लगाने के लिए विविधान उपायों का सहारा लिया किन्तु जनता को इस अन्तराल मंहगाई से कोई राहत न मिल सकी। कीमत वृद्धि का एक अन्य दुष्प्रभाव यह भी रहा कि 'बचत आय अनुपात' 10.5 प्रतिशत तक ही बढ़ सका।

<table>
<thead>
<tr>
<th>मद</th>
<th>खाद्यान्न</th>
<th>औऱक्कच्चा माल</th>
<th>और निर्मित माल</th>
<th>सभी वस्तुओं</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रतिशत वृद्धि</td>
<td>48.4</td>
<td>32.6</td>
<td>22.1</td>
<td>36.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

दूसरी योजना के अन्त में बेरोजगारों की संख्या 70 लाख थी। तीसरी योजना काल में श्रम शक्ति में 170 लाख की वृद्धि हुई परन्तु केवल 145 लाख लोगों को बेरोजगार दिलाया जा सका। इस प्रकार तीसरी योजना के अन्त में रोजी-रोटी की तलाश में भटकने वाले बेरोजगारों की संख्या लगभग 95 लाख थी।

18. बिभिन्न, एनएच विकास अभियान एवं आयोजन, तथा अन्य पाठ्यकृत, प्रोफेसर दिलीप दिलीप, दिल्ली-91, पृष्ठ 607-608.
4. मुख्य सुझावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया तथा एक नये किंतु आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की गई जोकि गरीब राज्यों की समस्या का समाधान करेगा।

<table>
<thead>
<tr>
<th>Resources Transferred to States and Union Territories (Rs. In Crores)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. States Share of Taxes and Duties</td>
</tr>
<tr>
<td>945</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Non Plan Assistance</td>
</tr>
<tr>
<td>a. Grants</td>
</tr>
<tr>
<td>1261</td>
</tr>
<tr>
<td>b. Loans</td>
</tr>
<tr>
<td>681</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Assistance for States and Union Territories Plan Schemes</td>
</tr>
<tr>
<td>a. Grants</td>
</tr>
<tr>
<td>743</td>
</tr>
<tr>
<td>b. Loans</td>
</tr>
<tr>
<td>504</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Assistance for Central Plans and Centrally Sponsored Schemes</td>
</tr>
<tr>
<td>a. Grants</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>b. Loans</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Total Grants &amp; Loans (2+3+4)</td>
</tr>
<tr>
<td>2183</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Less (Repayment of Loans and Advances)</td>
</tr>
<tr>
<td>850</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Net Resources Transferred</td>
</tr>
<tr>
<td>2278</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Excludes Rs. 421 Crores of loan assistance to state for clearance of over draft with RBI

---

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1966-74)

भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मौलिक रूप से 1 अप्रैल 1966 को प्रारम्भ की जानी थी किन्तु कुछ विशेष प्रकार की कठिनाइयों के कारण ऐसा करना सम्भव न हो सका। विदेशी पूंजी का उपयोग न होना, मूल्यों में लगातार वृद्धि के कारण बढ़ती हुई विकास लागतें, विदेशी विनियम का संकट, रूपये का अवृद्धि, सूचना अकाल के फलस्वरूप तृणीय योजना की असफलता विदेशी आक्रमण तथा आतंरिक साधनों की कमी के कारण चौथी योजना पूर्व निर्धारित समय पर प्रारंभ न की जा सकी। यदापि चौथी योजना का निर्माण कार्य सन् 1962 से प्रारंभ किया जा चुका था। परन्तु इसके प्रारूप को सन् 1966 तक अतिम रूप न दिया जा सका। ऐसी अवस्था में योजना आयोग के अध्यक्ष डा० गांधेगिरल के सुझावानुसार चतुर्थ योजना के निर्माण कार्य को कुछ काल के लिए स्थगित करके उसके स्थान पर मीन एक वर्षीय योजनायें चालू की गयी।

विकास निर्माण के रूप में अपनाई गयी यह तीन वार्षिक योजनायें अधिक सफल नहीं रहीं। निर्माण तकनीक अनुसार बने रहे और उद्देश्य भी पूरे न हो सके। उदाहरण के तौर पर 1966-67 में भारी सूचना के कारण खाद्यान्न उत्पादन 76 मिलियन टन तक ही पहुँच सका जोकि 1964-65 से 89 मिलियन से कहीं कम था। कृषि उत्पादन भी कम का औद्योगिक उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अर्थात् इसमें 1 प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई। बचत आय अनुपात 1965-66 के 10.3 प्रतिशत के स्तर से कम होकर, 1966-67 में 8.2 प्रतिशत रह गया। कीमत वृद्धि के सभी उपयोग विकास रहे, बल्कि 1966-67 में खोर कीमत सूचकांक में 14 प्रतिशत और 1967-68 में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई 1960-69 में कीमतों में 1 प्रतिशत की गिरावट देखने में आई। कुल मिलाकर भौगोलिक असफलता के बावजूद ये वार्षिक योजनायें विनियम विकास स्तरों पर इताल के स्थान पर समय बनाये रखने में अवसर सफल रही।

उपरुपक्त तीन वार्षिक योजनायें 31 मार्च 1969 को समाप्त हो गयी और इसके साथ-साथ कई वर्षों से स्थगित चौथी योजना का शी गणेश कर दिया गया। देश

की यह विशाल लेकिन असफल चौथी योजना अपने कार्यकाल 31 मार्च 1974 को समाप्त करके सदीव के लिए विदा हो चुकी है।

चौथी योजना के दौरान हुई प्रगति का अनुमान नीचे दी गई तालिका से लगाया जा सकता है। स्पष्ट है कि यह विशालकाय योजना एक-आध क्षेत्र को छोड़कर अधिक सफल नहीं कही जा सकती है। राष्ट्रीय आय के 5.5 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य के विशेष वास्तविक औसत वृद्धि 3.3 प्रतिशत रही। औद्योगिक विकास की दर 3.5 प्रतिशत वार्षिक आंकी गयी और अतिम वर्ष में तो इसकी विकास दर नकारात्मक हो गयी थी। औद्योगिक उत्पादन का 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लक्ष्य पूरा न हो सका। कृषि क्षेत्र की प्रगति भी सन्तोषजनक नहीं थी। खाद्यान्न का उत्पादन आशा से कम रहा। समग्र कृषि उत्पादन 29 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि लक्ष्य 5 प्रतिशत रहा था। बहुवर्षित हरित कृषि भी दम तोड़ चुकी थी। परन्तु गैरॉ उत्पादन में अवश्य वृद्धि हुई लेकिन चाँदल व अन्य फसलों का उत्पादन अत्यन्त निराशाजनक रहा।

### चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रगति के कुछ चुने हुये सूचक

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रंस्तर</th>
<th>मद (वार्षिक वृद्धि दर)</th>
<th>लक्ष्य</th>
<th>वास्तविक उपलक्ष्य</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>राष्ट्रीय आय</td>
<td>5.5</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>प्रति व्यक्ति आय</td>
<td>3.0</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>कृषि उत्पादन</td>
<td>5.0</td>
<td>2.9</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>औद्योगिक उत्पादन</td>
<td>8.0</td>
<td>4.7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>प्रति व्यक्ति उपभोग</td>
<td>2.5</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>सकल स्थायी निवेश</td>
<td>5.0</td>
<td>3.1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>निर्यात</td>
<td>7.0</td>
<td>5.0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>सकल पूंजी निर्माण : GDP का %</td>
<td>-</td>
<td>15.4</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>सकल देशी बचत: GDP का %</td>
<td>-</td>
<td>14.1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>विनियोग दर</td>
<td>14.5</td>
<td>13.0</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>विनियोग में घरेलू बचत का %</td>
<td>13.2</td>
<td>13.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
हमारी राय में चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन भौतिक लक्ष्यगत प्रगति (Physical Target Oriented Progress) के आधार पर अर्थव्यवस्था प्राप्त वृद्धि (Realised Increase) और आयोजित वृद्धि (Planned Increase) के आधार पर करना अधिक उचित होगा। इस दृष्टि से नीचे दी गयी तालिका में विभिन्न मदों के निष्पादन सूचकांक (Performance Index) तैयार किये गये हैं। आयोजित उत्पादन-वृद्धि की गणना करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के (1973–74 में) लक्ष्यों को 1968–69 कर्तित आधार स्तर उत्पादन में से घटाया गया है। इसी प्रकार प्राप्त उत्पादन के परिकल्पना हेतु पाचवी पंचवर्षीय योजना में वर्तमान प्राप्ति के आधार पर, 1973–74 में सम्मानित उत्पादन को आधार स्तर उत्पादन (1968–69) में से घटा दिया गया है। निष्पादन सूचकांक की परिभाषा वास्तविक उत्पादन वृद्धि के आयोजित उत्पादन-वृद्धि के प्रतिशत के रूप में की गई है।

निम्नलिखित तालिका को देखने से पता चलता है कि एक-आध मद जैसे सिंधित क्षेत्र, पैदलाइम व मसीनरी उत्पादन को छोड़कर शेष सूचकांक 20 से 30 प्रतिशत के बीच ही विवरण करता रहा है। आयोजित लक्ष्यों और प्राप्ति वृद्धि दरों में भारी अंतर कापाया जाना इस बात का प्रमाण है कि चौथी योजना। आयोजित लक्ष्यों के आधे ही एक प्राप्ति दरें में भारी अंतर कापाया जाना इस बात का प्रमाण है कि चौथी योजना। आयोजित लक्ष्यों के आधे ही एक प्राप्ति दरें में भारी अंतर कापाया जाना इस बात का प्रमाण है कि चौथी योजना।
राज्य की स्थापना, जो कि भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य था, की पूर्ति के लिए भी इन समस्याओं का समाधान करना जरूरी था। प्रथम योजना में रु 2378 करोड़ व्यय करने का निर्देश किया गया, लेकिन वास्तविक व्यय रु 1980 करोड़ ही हो सका।

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
(i) युद्ध एवं देश विमान से संसर्ग आर्थिक अस्तित्व का दूर करना।
(ii) प्रथम योजना में पूर्व की योजनाओं का लक्ष्य को पूरा करना।
(iii) एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ रहन-सहन का स्तर उच्चतर बनाया जा सके।

योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं का क्रम इस प्रकार था:
(i) इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया गया। कृषि के व्यवसाय विकास के लिए आथुत उपकरण, नियुक्ति, राष्ट्रीय खाद और सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना योजना का मुख्य उद्देश्य था।
(ii) कृषि के बाद दूसरा स्थान वित्त का अर्थात शक्ति के उत्पादन को दिया गया।
(iii) ग्रामीण श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के लिए सामुदायिक विकास योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया।
(iv) इसके अलावा सामाजिक कल्याण के कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, धिक्कत्सा व असामाजिक वृक्षा आदि के विकास को महत्व प्रदान किया गया ताकि मानवीय कल्याण और मानवीय पूर्णि निर्माण में वृद्धि हो सके।

राष्ट्रीय विकास परिषद और द्वितीय पंचवर्षीय योजना

20-21 जनवरी 1956 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। कुछ महत्वपूर्ण विषय जो राष्ट्रीय विकास परिषद के संशोधन के आये तथा को राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे।
(i) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के मूढांकन के लिए खाना तैयार किया गया।
(ii) निजी एवं राष्ट्रीय क्षेत्रों में विकास के लिए पूर्णि निवेश।

5. सिंह, एस.री.०, "आर्थिक विकास एवं योजना" एस्टेट एन.के. को संस्करण, नई दिल्ली-55, पृष्ठ संख्या 178-179
राष्ट्रीय विकास परिषद एवं पांचवीं पंचवर्षीय योजना

8—9 दिसंबर 1973 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक पांचवीं पंचवर्षीय योजना हेतु विचार विचारण के लिए सम्पन्न हुई।

राष्ट्रीय विकास परिषद की इस बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये:

1. पांचवीं पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता पूर्ति के लिये मूल्य विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा राज्यों को अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित करना। जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना है वे निम्न प्रकार हैं:
   (क) कृषि पर कर
   (ख) सिंचाई दरों का पुनर्मूल्यांकन
   (ग) विद्युत दरों का मूल्यांकन

2. राज्यों को कृषि क्षेत्र से अधिक कर प्राप्त करने के लिए समय अनुपलब्ध कार्यक्रमों को तथा राज्य कमेटी के सुझावों को लागू करना चाहिये। वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा उचित कर लगाया जाना चाहिये।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले सिंचाई दरों का राज्यों द्वारा पूर्ण मूल्यांकन होना चाहिये।

4. विज्ञान विभाग की योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन, उचित मात्रा में कर निर्धारित तथा घाटे की भरपूर के लिये राज्यों को उचित कदम उठाने चाहिये।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974—79)

पांचवीं योजना का निर्माण एवं कार्यकाल दोनों विवादास्पद रहे हैं। सर्वप्रथम योजना आयोग द्वारा 1972 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना का दाश्रीनिक आधार तैयार किया गया और इसका आधार रोजगार प्रचार था। इसके बाद सबसे बड़े सीधे सुझावादि के स्थान पर श्री हेमीश्री मंत्री के बाद राज्यों के सीधे सुझावों के स्थान पर श्री हेमीश्री मंत्री के बाद राज्यों को दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया, जिसका आधार रोजगार प्रचार से बदलकर उत्पादन प्रचार कर दिया गया। इस प्रदेश को 1972—73 की कीमत तृतीय के संदर्भ में एक

बार फिर संशोधित किया गया और इस प्रकार एक नया प्रलेख पौष्ची पंचवर्षीय योजना 1974–79 (प्रारूप) स्वीकृत किया गया। वैसे इस योजना को 1 अप्रैल 1974 से शुरु होकर 31 मार्च 1979 को खत्म होना था लेकिन 1977 में जनता सरकार ने शासन संभालने के बाद योजना का कार्यकाल एक वर्ष कम करके (1974–78) इसे 1978 में समाप्त कर दिया और उसके साथ ही अन्वेषण योजना के रूप में छोटी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। चूंकि जनता सरकार भूचाल की तरह आयी और ओपनी दोहरे की तरह चली गयी थी और शीघ्र ही कांग्रेस (ई) सरकार पदार्थ हो गयी थी, इसलिए पौष्ची पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूर्वक 5 साल (1974–79) ही मान लिया गया था।

पौष्ची पंचवर्षीय योजना को यद्यपि अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ा था तथापि कुछ क्षेत्रों में यह अस्तित्व सफल योजना सिद्ध हुई। योजनाकाल में वार्षिक विकास दर अर्थव्य न्यूप. 5.2 प्रतिशत से बढ़ा जबकि लक्ष्य 4.4 प्रतिशत वार्षिक रहा गया था।

<table>
<thead>
<tr>
<th>विकास मद</th>
<th>राष्ट्रीय आय</th>
<th>कृषि उत्पादन</th>
<th>आधुनिक उत्पादन</th>
<th>प्रति व्यक्ति उपयोग</th>
<th>सकल स्थाई निवेश</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>वार्षिक वृद्धि दर %</td>
<td>5.2</td>
<td>4.2</td>
<td>5.9</td>
<td>2.3</td>
<td>6.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

वर्षवार विकास दर क्रमशः 1.5, 9.8, 1.0, 8.8 तथा 5.1 प्रतिशत रही। कृषि उत्पादन तथा आधुनिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 4.2 तथा 5.9 प्रतिशत आंकी गयी और सकल स्थाई निवेश में 6.6 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि अनुमानित की गई।
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र0 सं0</th>
<th>यद</th>
<th>इकाई</th>
<th>आधारस्तर 1973–74</th>
<th>लक्ष्य 1978–79</th>
<th>प्राप्ति 1974–79</th>
<th>लक्ष्य 1974–79</th>
<th>वास्तविक 1974–78</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>खाद्यान्न</td>
<td>मिटन</td>
<td>105</td>
<td>125</td>
<td>132</td>
<td>3.5</td>
<td>3.7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>गन्ना</td>
<td>मिटन</td>
<td>144</td>
<td>161</td>
<td>152</td>
<td>2.7</td>
<td>2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>कपास</td>
<td>लाख गटटे</td>
<td>63</td>
<td>80</td>
<td>64</td>
<td>3.9</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>कोयला</td>
<td>मिटन</td>
<td>79</td>
<td>124</td>
<td>105</td>
<td>9.4</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>रुक्का पेट्रोलियम</td>
<td>मिटन</td>
<td>7</td>
<td>14</td>
<td>12</td>
<td>14.5</td>
<td>10.5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>सूती कस्त (कुल)</td>
<td>मिटन</td>
<td>7946</td>
<td>9500</td>
<td>9399</td>
<td>3.5</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>कागज व गाटा</td>
<td>हजार टन</td>
<td>776</td>
<td>1050</td>
<td>101</td>
<td>6.2</td>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>उर्वरक (N)</td>
<td>हजार टन</td>
<td>1058</td>
<td>2900</td>
<td>2180</td>
<td>22.3</td>
<td>18.1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>उर्वरक (P)</td>
<td>हजार टन</td>
<td>319</td>
<td>770</td>
<td>770</td>
<td>19.2</td>
<td>19.9</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>सीमेंट</td>
<td>मिटन</td>
<td>15</td>
<td>21</td>
<td>19</td>
<td>7.1</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>नस्ल</td>
<td>इस्पात</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>12.4</td>
<td>12.1</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>विधुत जनन</td>
<td></td>
<td>72</td>
<td>116</td>
<td>103</td>
<td>10.2</td>
<td>8.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

25. दल्ल एवं सुनद्रम "भारतीय अक्षयवस्था" एसी वर्ष 30 अडिली, नई दिल्ली–55, पृष्ठ संख्या–166
### Table 1

**Proposed Inter-State Distribution of Central Assistance for four years**

(1979-80/1982-83)

<table>
<thead>
<tr>
<th>States</th>
<th>Formula A</th>
<th>Formula B</th>
<th>Formula C</th>
<th>Formula D</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>(i) Special Category States</td>
<td>1800</td>
<td>1800</td>
<td>1800</td>
<td>1800</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) Other States</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Andhra Pradesh</td>
<td>367</td>
<td>311</td>
<td>321</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bihar</td>
<td>471</td>
<td>524</td>
<td>566</td>
<td>637</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Gujrat</td>
<td>214</td>
<td>220</td>
<td>200</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Haryana</td>
<td>106</td>
<td>85</td>
<td>72</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Karnataka</td>
<td>229</td>
<td>251</td>
<td>232</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Kerala</td>
<td>166</td>
<td>135</td>
<td>146</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Madhya Pradesh</td>
<td>370</td>
<td>399</td>
<td>394</td>
<td>423</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Maharashtra</td>
<td>447</td>
<td>387</td>
<td>340</td>
<td>307</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Orissa</td>
<td>151</td>
<td>195</td>
<td>197</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Punjab</td>
<td>140</td>
<td>106</td>
<td>88</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Rajasthan</td>
<td>242</td>
<td>240</td>
<td>231</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Tamil Nadu</td>
<td>276</td>
<td>264</td>
<td>284</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Uttar Pradesh</td>
<td>717</td>
<td>816</td>
<td>845</td>
<td>794</td>
</tr>
<tr>
<td>14. West Bengal</td>
<td>304</td>
<td>267</td>
<td>284</td>
<td>312</td>
</tr>
<tr>
<td>(III) Total II States</td>
<td>4200</td>
<td>4200</td>
<td>4200</td>
<td>4200</td>
</tr>
<tr>
<td>(IV) Total (II+II) States</td>
<td>6000</td>
<td>6000</td>
<td>6000</td>
<td>6000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 90% of the amount is distributed on the basis of population, PerCapita income, tax effort and continuing power and major and medium irrigation projects and the balance 10% is distributed in the same proportion as the 90% component.26

---

<table>
<thead>
<tr>
<th>States</th>
<th>Formula A</th>
<th>Formula B</th>
<th>Formula C</th>
<th>Formula D</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(I) Special Category States</td>
<td>2301</td>
<td>2301</td>
<td>2301</td>
<td>2301</td>
</tr>
<tr>
<td>(II) Other States</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Andhra Pradesh</td>
<td>1975</td>
<td>1919</td>
<td>1929</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bihar</td>
<td>1872</td>
<td>1925</td>
<td>1967</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Gujrat</td>
<td>1681</td>
<td>1687</td>
<td>1667</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. Haryana</td>
<td>845</td>
<td>824</td>
<td>811</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. Karnataka</td>
<td>1649</td>
<td>1671</td>
<td>1652</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. Kerala</td>
<td>938</td>
<td>907</td>
<td>918</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. Madhya Pradesh</td>
<td>2019</td>
<td>2048</td>
<td>2043</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Maharashtra</td>
<td>3934</td>
<td>3874</td>
<td>3827</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Orissa</td>
<td>667</td>
<td>711</td>
<td>713</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. Punjab</td>
<td>1205</td>
<td>1171</td>
<td>1153</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Rajasthan</td>
<td>960</td>
<td>958</td>
<td>949</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Tamil Nadu</td>
<td>1757</td>
<td>1745</td>
<td>1765</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13. Uttar Pradesh</td>
<td>3845</td>
<td>3944</td>
<td>3973</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14. West Bengal</td>
<td>1882</td>
<td>1845</td>
<td>1862</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(III) Total II States</td>
<td>25229</td>
<td>25229</td>
<td>25229</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(IV) Total (I+II) States</td>
<td>27530</td>
<td>27530</td>
<td>27530</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Table-3

Estimated Central Assistances and Total Plan outlay per capita for Four Year\(^2\) (1979-80/1982-83)

<table>
<thead>
<tr>
<th>States</th>
<th>Percapita Central assistance(^1)</th>
<th>Percapita Plan Outlay(^2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>A</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>(I) Special Category States</td>
<td>665</td>
<td>665</td>
</tr>
<tr>
<td>(II) Other States</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Andhra Pradesh</td>
<td>84</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bihar</td>
<td>84</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Gujrat</td>
<td>80</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Haryana</td>
<td>106</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Karnataka</td>
<td>78</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Karala</td>
<td>78</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Madhya Pradesh</td>
<td>89</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Maharastra</td>
<td>89</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Orissa</td>
<td>69</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Punjab</td>
<td>103</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Rajasthan</td>
<td>94</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Tamil Nadu</td>
<td>67</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Uttar Pradesh</td>
<td>81</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>14. West Bengal</td>
<td>69</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>(III) Total II States</td>
<td>82</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>(IV) Total (I+II) States</td>
<td>111</td>
<td>111</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Total Central Assistance as in Table 1
2. Total Plan outlay as in Table 2

---

28. Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-III Government of India Planning Commission पुष्प संग्रहा-266

105
Table-4

Estimated Central Assistance and States Plan outlay Per Capita for Five Year of Fifth Plan and Five Year Plan\textsuperscript{29}

| States | Percapita Central assistance\textsuperscript{1} |  |  |  |  | Percapita Plan Outlay\textsuperscript{2} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Fifth Plan 1978-83 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| (I) Special Category States |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 814 | 814 | 814 | 814 | 535 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |  |  |  |  |  |
| (II) Other States |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Andhra Pradesh | 84 | 126 | 113 | 111 | 116 | 303 | 550 | 537 | 534 | 539 |  |  |  |  |  |
| 2. Bihar | 84 | 114 | 124 | 144 | 131 | 230 | 400 | 410 | 430 | 417 |  |  |  |  |  |
| 3. Gujrat | 79 | 108 | 110 | 98 | 102 | 436 | 754 | 756 | 745 | 749 |  |  |  |  |  |
| 4. Haryana | 99 | 152 | 132 | 109 | 118 | 597 | 1046 | 1025 | 1002 | 1012 |  |  |  |  |  |
| 5. Karnataka | 79 | 109 | 116 | 109 | 109 | 332 | 662 | 669 | 662 | 663 |  |  |  |  |  |
| 6. Kerala | 111 | 122 | 108 | 122 | 113 | 265 | 520 | 506 | 521 | 511 |  |  |  |  |  |
| 7. Madhya Pradesh | 78 | 125 | 131 | 137 | 130 | 330 | 583 | 590 | 596 | 589 |  |  |  |  |  |
| 8. Maharashtra | 66 | 122 | 110 | 94 | 101 | 465 | 925 | 913 | 897 | 904 |  |  |  |  |  |
| 9. Orissa | 104 | 110 | 130 | 145 | 131 | 264 | 389 | 409 | 424 | 410 |  |  |  |  |  |
| 10. Punjab | 97 | 141 | 115 | 83 | 102 | 747 | 1080 | 1055 | 1022 | 1042 |  |  |  |  |  |
| 11. Rajasthan | 106 | 133 | 132 | 113 | 128 | 269 | 461 | 460 | 440 | 456 |  |  |  |  |  |
| 12. Tamil Nadu | 72 | 99 | 96 | 105 | 101 | 272 | 500 | 497 | 506 | 502 |  |  |  |  |  |
| 13. Uttar Pradesh | 89 | 118 | 129 | 127 | 133 | 276 | 520 | 531 | 529 | 535 |  |  |  |  |  |
| 14. West Bengal | 68 | 97 | 89 | 99 | 93 | 281 | 508 | 500 | 510 | 503 |  |  |  |  |  |
| (III) Total II States | 84 | 117 | 117 | 117 | 117 | 325 | 588 | 588 | 588 | 588 |  |  |  |  |  |
| (IV) Total (I+II) States | 101 | 152 | 152 | 152 | 152 | 335 | 610 | 610 | 610 | 610 |  |  |  |  |  |

1. Total Assistance for 1978-79 as in the annual Plan for 1979-83 as in Table-1
2. Total Plan outlay for 1978-79 as in the annual Plan for 1979-83 as in Table-2

\textsuperscript{29} Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-III Government of India Planning Commission घोषणा 387–287

106
### Table-5
Percentage Shares of States in Central Assistance and Plan Outlay
Fifth Plan 1974-79 and Plan 1978-83

<table>
<thead>
<tr>
<th>States</th>
<th>Central assistance&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;</th>
<th>Plan 1978-83</th>
<th>Plan Outlay&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;</th>
<th>Plan 1978-83</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Fifth Plan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Andhra Pradesh</td>
<td>8.54</td>
<td>9.16</td>
<td>8.22</td>
<td>8.01</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bihar</td>
<td>10.99</td>
<td>10.74</td>
<td>11.63</td>
<td>13.50</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Haryana</td>
<td>2.31</td>
<td>2.55</td>
<td>2.20</td>
<td>1.82</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Karnataka</td>
<td>5.41</td>
<td>5.30</td>
<td>5.67</td>
<td>5.30</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Maharashtra</td>
<td>7.78</td>
<td>10.23</td>
<td>9.22</td>
<td>7.90</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Orissa</td>
<td>5.33</td>
<td>4.03</td>
<td>4.76</td>
<td>5.32</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Punjab</td>
<td>3.08</td>
<td>3.18</td>
<td>2.61</td>
<td>1.87</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Rajasthan</td>
<td>6.36</td>
<td>5.70</td>
<td>5.66</td>
<td>4.83</td>
</tr>
<tr>
<td>14. West Bengal</td>
<td>7.01</td>
<td>7.19</td>
<td>6.58</td>
<td>7.34</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total 14 Staes</strong></td>
<td><strong>100.00</strong></td>
<td><strong>100.00</strong></td>
<td><strong>100.00</strong></td>
<td><strong>100.00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Total assistance for 1978-79 as in the Annual Plan and for 1979-83 as in Table-1
2. Total Plan Outlay for 1978-79 as in the Annual Plan and for 1979-83 as in Table-2

---

30. Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-III Government of India Planning Commission योजना परिषद के बैठकों के दस्तावेज़ विभाग भीमें-288

107
Table-6

Proposed Central Assistance for Four Year 1979-83 Percentage Distribution\textsuperscript{31}

<table>
<thead>
<tr>
<th>States</th>
<th>Central assistance\textsuperscript{1}</th>
<th>Central Assistance Plus Market Borrowing on Present Basis\textsuperscript{2}</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>A</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Andhra Pradesh</td>
<td>8.74</td>
<td>7.40</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bihar</td>
<td>11.22</td>
<td>12.48</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Gujrat</td>
<td>5.10</td>
<td>5.25</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Haryana</td>
<td>2.52</td>
<td>2.03</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Karnataka</td>
<td>5.45</td>
<td>5.98</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Madhya Pradesh</td>
<td>3.81</td>
<td>9.49</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Maharashtra</td>
<td>10.64</td>
<td>9.20</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Orissa</td>
<td>3.60</td>
<td>4.64</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Punjab</td>
<td>3.33</td>
<td>2.51</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Rajasthan</td>
<td>5.76</td>
<td>5.72</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Tamil Nadu</td>
<td>6.57</td>
<td>6.29</td>
</tr>
<tr>
<td>Total 14 Staes</td>
<td>95.00</td>
<td>100.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. Total assistance as in Table-1. Percentage Shares in Market borrowing to be the same as in other assistance.

2. Total assistance as in Table1 plus borrowing distributed as at present.

\textsuperscript{31} Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-III Government of India Planning Commission पृष्ठ संख्या-289

108
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)

छठी पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए थे:
1. अर्थव्यवस्था की विकास दर में सार्वजनिक वृद्धि संसाधनों के प्रयोग में कुशलता को बढ़ाना और उत्पादकता में वृद्धि करना।
2. गरीबी और बेरोजगारी में उत्तरोत्तर कमी लाना।
3. आर्थिक तकनीक आलोचना प्राप्त करने हेतु आधुनिकीकरण पर बल देना।
4. कर्जों के घरेलू संसाधनों का रूपी संबंध करना।
5. अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के रूप में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना।
6. नृपति आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि के माध्यम से कमजोर लोगों के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार करना।
7. सार्वजनिक नीतियों और वितरण प्रणाली को गरीबों के अनुकूल बनाना ताकि आय और समाज की विधेयकों में कमी आय।
8. स्वीकृतिकारी रूप से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना।
9. उपर्युक्त शिक्षा, संचार और संसाधनात्मक कार्य नीतियों के द्वारा विकास प्रक्रिया में जनता के सभी क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना।
10. परिशिष्टतक और पर्यावरणीय, परिस्थितियों के संकेत और सुधार पर बल देना, जिससे कि आर्थिक विकास के अन्यथा और दीर्घकालिक लक्ष्यों के शीर्ष सामाजिक रख जा सके।

छठी पंचवर्षीय योजना ऐसे समय पर चालू की गई थी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर से गुजर रही थी। योजना की पूर्व संख्या की प्रमुख कठिनाइयों ये थी कि वर्ष 1979–80 का सुख, स्वीकृति की उच्च दर, तेल की आयोजनों में भारी वृद्धि के कारण जीवन की शरीर में एक सीधी और तेज गिरावट। परन्तु प्रशासन की बात यह है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद छठी योजना ने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। सालों योजना ने इस तथ्य पर स्वीकार करते हुए कहा कि "कुल भिन्न छठी योजना का देश की संवृद्धि की गति को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय में भारी कोशिश है।"
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्षेत्र योजना का लक्ष्य</th>
<th>कृषि</th>
<th>विनिमय व खनन</th>
<th>सेवा क्षेत्र</th>
<th>कुल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>योजना का लक्ष्य</td>
<td>3.8</td>
<td>6.9</td>
<td>5.5</td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td>वास्तविक वृद्धि दर</td>
<td>4.3</td>
<td>3.7</td>
<td>6.6</td>
<td>5.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र0</th>
<th>मद</th>
<th>परिवहन मौलिक अनुमान</th>
<th>परिवहन वास्तविक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>सं0</td>
<td></td>
<td>करोड़ ₹0</td>
<td>प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>कृषि</td>
<td>5695</td>
<td>5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ग्राम विकास</td>
<td>5364</td>
<td>5.5</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</td>
<td>1480</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>सिंचाई एवं बादलनियंत्रण</td>
<td>12160</td>
<td>12.5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>उद्योग</td>
<td>26535</td>
<td>27.2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>उद्योग एवं खनिज</td>
<td>15018</td>
<td>15.4</td>
</tr>
<tr>
<td>a</td>
<td>ग्राम तथा लघु उद्योग</td>
<td>1781</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>b</td>
<td>बड़े एवं मध्यम उद्योग</td>
<td>13237</td>
<td>13.6</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>परिवहन</td>
<td>12412</td>
<td>12.7</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>संचार एवं प्रसारण</td>
<td>3134</td>
<td>3.2</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>विज्ञान एवं तकनीकी</td>
<td>865</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>सामाजिक सेवायें</td>
<td>14035</td>
<td>14.4</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>विविध</td>
<td>802</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल  (1 से 11)</td>
<td>97500</td>
<td>100.00</td>
<td>109292</td>
</tr>
</tbody>
</table>

नोट: योजना कार्य में प्राकृतिक विपदों पर हुये 1175 करोड़ ₹0 के विनिमय को मिलाकर, कुल परिवहन ₹0 1,10,467 करोड़ होता है।

34. सिंह, एस.पी. “आर्थिक विकास एवं नियोजन” एस.पी. प्रदर्शन को नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-204
राष्ट्रीय विकास परिषद एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक 8-9 नवम्बर 1985 को सम्पन्न हुई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का परिवर्तन तथा निवेश

1984-85 की कीमतों पर

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>मद</th>
<th>करोड़ रु.</th>
<th>कुल का प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>सार्वजनिक क्षेत्र का परिवहन</td>
<td>180000</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>चालू परिवहन</td>
<td>25782</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश (1-2)</td>
<td>154218</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>निजी क्षेत्र का निवेश</td>
<td>168148</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>कुल निवेश (3-4)</td>
<td>322366</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

केंद्र राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों की योजना राशि

<table>
<thead>
<tr>
<th>परिवहन (करोड़ रु.)</th>
<th>केंद्रीय सरकार</th>
<th>राज्य सरकारें</th>
<th>केंद्रशासित क्षेत्र</th>
<th>योग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रस्तावित परिवहन</td>
<td>95534</td>
<td>80698</td>
<td>3768</td>
<td>180000</td>
</tr>
<tr>
<td>वास्तविक परिवहन</td>
<td>130714</td>
<td>87719</td>
<td>7504</td>
<td>225937</td>
</tr>
</tbody>
</table>

छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना में बचत तथा निवेश

समावेश आयाम

करोड़ रु। 1984-85 की कीमतों पर

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>मद</th>
<th>करोड़ रु। 1984-85</th>
<th>करोड़ रु। 1989-90</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>सकल घरेलू उतपाद (GDP)</td>
<td>217762</td>
<td>281945</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>सकल घरेलू पूंजी निर्माण (GDLF)</td>
<td>53338</td>
<td>72997</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>सकल घरेलू बचत (GDS)</td>
<td>50738</td>
<td>68997</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>निवेश दर (2/1X100)</td>
<td>24.5</td>
<td>25.9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>बचत दर (3/1X100)</td>
<td>23.3</td>
<td>24.5</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>वर्तमान पूंजी उत्पादन अनुपात (ICOR)</td>
<td>4.9</td>
<td>5.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

35. Summary Record of discussion of the National Development Council meetings Vol-IV (36th - 44th) Government of India Planning Commission पृष्ठ संख्या-79

111
सातावी पंचवर्षीय योजना (1985–90)

सातावी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 9 नवम्बर 1985 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। जबकि छठी पंचवर्षीय योजना बेहद कठिन परिस्थितियों में शुरू की गई थी, सातवी योजना की प्रारंभिक दशक एंड काफी अनुकूल थी। छठी योजना के शुरू में, हमारी अर्थव्यवस्था काफी नाजुक स्थिति में थी। सन 1979 के महाकर्षण सूखे के फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में 17 प्रतिशत मिराबल आई और शुद्ध देशीय उत्पाद (N.D.P.) में 6 प्रतिशत की कमी दर की गई। तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होने से युगातन रोज दर सी अधिक प्रगति और लक्षित वृद्धि दर को खतरनाक पैदा हो चुकी थी। उच्च स्तरीय दर से आर्थिक प्रगति और लक्षित वृद्धि दर को खतरा पैदा हो चुका था। परन्तु प्रसन्नता की बात यह था कि इस प्रतिकूल दशकों में प्रायदृष्टि पर ३०% छठी योजना ‘मील का एक पत्थर’ सिद्ध हुई। अतः सातवी योजना की पूर्व संध्या पर बिना का कोई कारण नहीं था, क्योंकि छठी योजना से विरासत में मिली सुखद दशकएं, उसकी सफल उदाहरण के लिए, प्रमुख थीं।

भारतीय अर्थव्यवस्था और आयोजन के चार मंगलवारी सिद्धान्त रहे हैं — तीव्र विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। सातवी योजना के सुपरेखा भी लगभग इन्हीं मूल उद्देश्यों को सामने रखकर तैयार की गयी थी और इतने प्रमुख उद्देश्य थे:

1. एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर आर्थिक विकास निर्माण करना।
2. कमालता (Equity) एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रगति की स्थापना करना।
3. आर्थिक तथा सामाजिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना।
4. देशीय टेकनोलॉजी के विकास के लिए एक सुदृढ आधार तैयार करना।

यह अनुमान विचारित किया गया कि पिछले कई दशकों के दौरान सामाजिक न्याय सबभी प्रगति अधिक उन्नति करने वाली की अनुकूलित थी। इसलिए सामाजिक न्याय विकास के लिए उपलब्ध रोजगार की लोकता सामाजिक नीति का केंद्र किन्नू था। क्योंकि सातवी रोजगार तथ्यानुसार रोजगार का काम रखा जा सकता है जब वह उच्चाधिकारी देशीय उत्पादक हो और उत्पादक एवं आय में लगातार वृद्धि करता हो। फिर सातवी योजना का उद्देश्य राज्यों में ग्रीष्म की वृद्धि करना था और इसकी पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन...
विशेषकर खाद्यानुष्ठान उत्पादन की बढ़ता आवश्यक समझा गया।

**आत्मनिर्भर योजना की प्रगति के अभिसूचक**

<table>
<thead>
<tr>
<th>मद</th>
<th>आधार वर्ष</th>
<th>1984-85</th>
<th>1989-90</th>
<th>वापसी चक्रवृद्धि दर 1985-90</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रति व्यक्ति आय (रु.)</td>
<td>1980-81</td>
<td>133808</td>
<td>175400</td>
<td>5.5</td>
</tr>
<tr>
<td>जीडीपी का दर 1985-90</td>
<td>1980-81</td>
<td>1811</td>
<td>2134</td>
<td>3.4</td>
</tr>
<tr>
<td>कृषि उत्पादन सूचकांक</td>
<td>1980-81</td>
<td>130.7</td>
<td>196.4</td>
<td>8.6</td>
</tr>
<tr>
<td>कृषि उत्पादन सूचकांक</td>
<td>1969-70</td>
<td>154.6</td>
<td>187.0</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>सकल घरेलू पूंजी निर्माण (GDP का %)</td>
<td>-</td>
<td>19.6</td>
<td>27.3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>सकल घरेलू व्यय का दर (GDP का %)</td>
<td>-</td>
<td>18.2</td>
<td>24.6</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>खाद्यानुष्ठान उत्पादन (मिल्टन)</td>
<td>-</td>
<td>145.5</td>
<td>171.0</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>तेल (रु. 100)</td>
<td>चालू मूल्य</td>
<td>117744</td>
<td>27681</td>
<td>18.7</td>
</tr>
<tr>
<td>आयात (रु. 100)</td>
<td>चालू मूल्य</td>
<td>17134</td>
<td>35416</td>
<td>15.6</td>
</tr>
<tr>
<td>उपभोक्ता मूल्य सूचकांक</td>
<td>1982=00</td>
<td>118</td>
<td>173</td>
<td>9.4</td>
</tr>
<tr>
<td>ध्वे मूल्य सूचकांक</td>
<td>1981-82=100</td>
<td>120</td>
<td>166</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>क्लासिक संसाधन (रु. 100)</td>
<td>M³</td>
<td>102357</td>
<td>230950</td>
<td>18.5</td>
</tr>
<tr>
<td>विदेशी मुद्रा भण्डार (रु. 100)</td>
<td>-</td>
<td>6817</td>
<td>5787</td>
<td>-10.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**आत्मनिर्भर योजना के दौरान संवृद्धि-दरों की प्रगति**

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्षेत्र</th>
<th>लक्ष्य 1985-90</th>
<th>उपलब्धि 1985-90</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>कृषि</td>
<td>2.5</td>
<td>3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>खनन</td>
<td>11.7</td>
<td>8.1</td>
</tr>
<tr>
<td>भिन्नविश</td>
<td>5.5</td>
<td>7.5</td>
</tr>
<tr>
<td>परिवहन, संचार तथा व्यापार</td>
<td>7.1</td>
<td>6.4</td>
</tr>
<tr>
<td>सामूहिक वैज्ञानिक सेवाएं</td>
<td>6.1</td>
<td>6.0</td>
</tr>
<tr>
<td>सभी क्षेत्र</td>
<td>5.0</td>
<td>5.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

36. शिपान, एमएल. "विकास का अर्थशास्त्र पर आवागमन" पृष्ठ संख्या–610–611
37. Economic Survey Govt. of India 1992-93 पृष्ठ संख्या–5-1

113
### कृषि उत्पादन: लक्ष्य तथा उपलब्धि

<table>
<thead>
<tr>
<th>मद</th>
<th>ईकाई</th>
<th>आधार 1984-85</th>
<th>संशोधित लक्ष्य</th>
<th>उपलब्धि 1989-90</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>खाद्यान्न</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>150</td>
<td>174-76</td>
<td>171.0</td>
</tr>
<tr>
<td>मैदाभ</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>45</td>
<td>56</td>
<td>49.8</td>
</tr>
<tr>
<td>मोट अनाज</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>32</td>
<td>34-35</td>
<td>34.8</td>
</tr>
<tr>
<td>दालें</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>13</td>
<td>14-15</td>
<td>12.8</td>
</tr>
<tr>
<td>चावल</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>60</td>
<td>72-73</td>
<td>73.6</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रमुख तिलहन</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>13</td>
<td>16-18</td>
<td>16.9</td>
</tr>
<tr>
<td>गन्ना</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>180</td>
<td>206</td>
<td>225.6</td>
</tr>
<tr>
<td>कपास</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>7.5</td>
<td>8.5</td>
<td>11.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### सावधी योजना: औद्योगिक उत्पादन: लक्ष्य और उपलब्धि

<table>
<thead>
<tr>
<th>को</th>
<th>सं</th>
<th>योजना</th>
<th>लक्ष्य 1989-90</th>
<th>योजना 1989-90</th>
<th>वाष्पीकरण चक्रवृद्धि दर (लक्ष्य)</th>
<th>वाष्पीकरण उत्पादन 1989-90</th>
<th>चक्रवृत्त उत्पादन 1989-90</th>
<th>चक्रवृत्त उत्पादन 1985-90</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>कोयला</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>226</td>
<td>8.9</td>
<td>201</td>
<td>6.4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>राज तेल</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>34.6</td>
<td>3.6</td>
<td>34.1</td>
<td>3.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>कच्चा तेल</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>58.1</td>
<td>6.6</td>
<td>50.6</td>
<td>3.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>रिस्लाइग औद्योगिक</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>12.64</td>
<td>7.6</td>
<td>13.0</td>
<td>8.2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>लाइट्रेक्टेंट</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>6.56</td>
<td>10.9</td>
<td>6.74</td>
<td>11.4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>पाटन निर्यात</td>
<td>000 टन</td>
<td>4625</td>
<td>3.5</td>
<td>1304</td>
<td>-1.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>कांग्रेस विज्ञान</td>
<td>000 टन</td>
<td>1800</td>
<td>5.7</td>
<td>1823</td>
<td>6.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td>हिन्दी</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>10.2</td>
<td>10.5</td>
<td>10.99</td>
<td>12.9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td>वनस्पति</td>
<td>000 टन</td>
<td>1210</td>
<td>5.6</td>
<td>939</td>
<td>0.2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td></td>
<td>सीमेंट</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>49</td>
<td>10.2</td>
<td>45.8</td>
<td>8.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td>कपड़ा (दौड़ी क्षेत्र)</td>
<td>ब्रांडमामर</td>
<td>14.5</td>
<td>3.9</td>
<td>18.2</td>
<td>9.2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td>टेस्टर</td>
<td>हजार</td>
<td>135</td>
<td>9.7</td>
<td>125</td>
<td>8.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
<td>मशीन ट्रूल्स</td>
<td>करोड़</td>
<td>500</td>
<td>10.5</td>
<td>652</td>
<td>16.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td></td>
<td>रेलवे ट्रेफिक</td>
<td>मिल्टन</td>
<td>340</td>
<td>5.3</td>
<td>334</td>
<td>4.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td></td>
<td>विद्युत जनन</td>
<td>बिक्वेट्थ पहुँच</td>
<td>295</td>
<td>12.1</td>
<td>268.4</td>
<td>9.4</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

38. Economic Survey Govt. of India 1982-83, पृष्ठ संख्या-S-18
39. वही पृष्ठ संख्या- S-33-39
सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यापार तथा भुगतान शेष की स्थिति

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>नियायत</td>
<td>10895</td>
<td>12452</td>
<td>15674</td>
<td>20232</td>
<td>27681</td>
</tr>
<tr>
<td>आयात</td>
<td>19658</td>
<td>20096</td>
<td>22244</td>
<td>28235</td>
<td>35416</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यापार शेष</td>
<td>-8763</td>
<td>-7644</td>
<td>-6570</td>
<td>-8003</td>
<td>-7735</td>
</tr>
<tr>
<td>चालू खाते पर व्यापार शेष</td>
<td>-5927</td>
<td>-5830</td>
<td>-6293</td>
<td>-10410</td>
<td>-9824</td>
</tr>
<tr>
<td>चालू खाते पर धाटा (as % of GDP)</td>
<td>-2.3</td>
<td>-2.0</td>
<td>-1.9</td>
<td>-3.0</td>
<td>-2.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

सावती पंचवर्षीय योजना में मूल्य सूचकांक (नयी श्रंखला) 40

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्ष</th>
<th>धारा मूल्य सूचकांक 1981-82=100</th>
<th>प्रतिष्ठात परिवर्तन वार्षिक स्फीति दर %</th>
<th>उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक सूचकांक)</th>
<th>प्रतिष्ठात परिवर्तन वार्षिक स्फीति दर %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1984-85</td>
<td>120</td>
<td></td>
<td>118</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1985-86</td>
<td>125</td>
<td>4.7</td>
<td>126</td>
<td>6.7</td>
</tr>
<tr>
<td>1986-87</td>
<td>133</td>
<td>5.8</td>
<td>137</td>
<td>7.8</td>
</tr>
<tr>
<td>1987-88</td>
<td>144</td>
<td>9.4</td>
<td>149</td>
<td>10.9</td>
</tr>
<tr>
<td>1988-89</td>
<td>154</td>
<td>6.3</td>
<td>166</td>
<td>8.5</td>
</tr>
<tr>
<td>1989-90</td>
<td>166</td>
<td>8.1</td>
<td>173</td>
<td>5.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

40. Economic Survey Govt. of India 1992-93 पुंडरिक संजय–8-64-89

115
8वीं पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय विकास परिषद

शोध का विषय क्षेत्र 1992 से 2005 तक होने के कारण इस दीर्घांक स्वीकृत हुई पंचवर्षीय योजनायें 8वीं, 9वीं एवं 10वीं से समाप्तित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। जो इस प्रकार है—

राष्ट्रीय विकास परिषद की 44वीं बैठक—

राष्ट्रीय विकास परिषद की 44वीं बैठक 22-23 मई 1992 को प्रधानमंत्री श्री पी.वी.0 नरसिंह राव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) पर विचार विमर्श किया गया।

7(VI) - 44वीं बैठक में यह कहा कि विकास की प्रक्रिया में जनता द्वारा कार्य किया जायेगा तथा सरकार के केंद्र सहयोग करेगी।

(23) प्रणव मुखर्जी द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अंतिम बैठक के बाद प्रधानमंत्री कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे - जनसंख्या निगमण, रोजगार मुहैया करना, साक्षरता तथा योजनाओं के विकास करण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की सहमतियों का निर्माण किया जायेगा।

(40) प्रधानमंत्री द्वारा परिषद का ध्यान कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी आकृष्ट कराया गया है जैसे केंद्र सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए जैसे - सरकारी खेती को कम करना, सरकारी बांध बनाने में सुधार आदि। यही कार्य राज्य को भी करना चाहिए।

(45) आंत्र्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी ने कहा कि निजी क्षेत्र आउटल (Public Sector Outlay) का 41% ही केंद्र सरकार के साथ (State Plan Outlay) को दिया जाना है। यही विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में रखा गया।

(58) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गौंधोक अयांग ने कहा - राज्य आदान-प्रदान स्तर उच्च हैं तथा मुख्य माग्न से कटे हुए हैं। राज्य में कोई राष्ट्रीय योजना (National Project) राज्य में नहीं है।

(1) Summary Record of the Discussions held at the Forty Fourth meeting of the National Development Council on May 22-23, 1992
(2) Summary Record of Discussion of the National Development Council meeting Vol IV (36th to 44th meetings)
Govt of India Planning Commission P-362
(3) I bid P-367
(4) I bid P-370
(5) I bid P-372

116
(61) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे.जो जयललिता ने कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाया। स्तर जल असुरक्षियों तथा आंतरिक जल असुरक्षियों का मुद्दा उठाया गया है।
(69) पं. भंगल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु है जो हां तो पूर्वी राज्यों में ऊर्जा का संकट है?
(75) बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने कहा है श्री योजना राज्य के प्रस्तावित आउटलर तथा भौगोलिक अन्तर्गत तथा कर्मकांड के आधार पर नहीं बनी है।
(86) गुजरात के मुख्यमंत्री श्री चिराग बाई पटेल ने कहा कि राज्य सरकार को आर्थिक समस्या है तथा जो योजना चल रही है; राज्य उनके लिए वाह्य सहायता भी नहीं दे पाते हैं। जिसके लिए राज्य का विशेष सहायता मिलनी चाहिए।
(96) मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री आरकेएस दोंदे शिंह ने कहा कि मणिपुर विकास कार्यक्रमों में बहुत पीछे है तथा राज्य आयार मूल संरचनाओं में भी अन्य राज्यों से पीछे है।
(99) नेपाल के मुख्यमंत्री श्री जीवेनेव वायाग ने कहा कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को विशेष वित्तीय परिस्थितियों का समान करना पड़ता है तथा यह प्रक्रिया नवीं वित्त आयोग का परिणाम है।
(103) नागालैण्ड के मुख्यमंत्री श्री लोकनाथ भिन्न ने कहा नागालैण्ड एक ऐसा राज्य है जो स्थापना के समय से ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्य वित्तीय समानताओं से सर्वाधिक है, जिसका कारण केंद्रीय सहायता ढूँचा कार्यक्रम (Pattern of Central Assistance) जो कि 1989-90 में लागू किया गया।
(107) हिमालय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शान्ता कुमार ने कहा कि जब 10वीं वित्त आयोग की स्थापना में राज्यों की भी लागू होनी चाहिए। तभी राज्यों की आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
(112) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं केंद्र आर्थिक व सामाजिक प्रगति के लिए सहायता नहीं होती है।

(6) Summay Record of Discussion of the National Development Council meeting Vol IV (36th to 44th meeting)
Govt of India Planning Commission P-374
(7) I bid P-376
(8) I bid P-378
(9) I bid P-381
(10) I bid P-383
(11) I bid P-384
(12) I bid P-385
(13) I bid P-386
(14) I bid P-387
इस प्रकार 45वीं बैठक में विभिन्न राज्यों द्वारा इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

6वीं योजना
राष्ट्रीय विकास परिषद की 45वीं बैठक
राष्ट्रीय विकास परिषद की 45 वीं बैठक 5 अप्रैल 1993 को सम्पन्न हुई, जिसकी अयोध्या प्रधानमंत्री श्री पीयूष नरसिंहसाराव ने की।
(1) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के अन्त में उपाध्यक्ष योजना आयोग श्री प्रणव मुखर्जी के द्वारा उन मुद्दों को घोषित किया गया जो अन्ततः इस बैठक के विचार विमर्श के परिणाम थे।
31.2 (i) सामान्यतः समापन हुआ किन्तु फिर भी एक विचार सर्व सहमति से सामने आया कि इस विस्तृत बैठक के बारिश भी कुछ तथ्य विचारार्थी सूची से बाहर रह गये तथा यह निर्णय हुआ कि यह अयोध्या योजना आयोग के अधिकार में दे दिया जाए।
(ii) औद्योगिक कमेटी के सुझावों जो राष्ट्रीय विस्तृत बॉर्ड (SEB'S) के संदर्भ में ये उनके पूर्ण आलोचनात्मक तरीके से विचार विमर्श किया गया।

व्यस्ततः विस्तृत प्रबंधक विकास की आयोगी संचालन है तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यह स्वीकार किया गया कि विस्तृत क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए सर्वाधिकार कार्यक्रम चलाए जाने चाहिये। अतः यह निर्णय हुआ कि उर्जा (Power) के सर्वाधिकार

31.3 विकास क्षेत्र के दीर्घकालिक निर्माण के लिए एक कमेटी बननी चाहिये जो राष्ट्रीय विकास परिषद के अधीन कार्य करेगी। यह कमेटी उन सभी आत्मनिर्भर संस्थाओं को नियंत्रित करेगी जो राज्य विस्तृत बॉर्ड के अधीक्षक पहलुओं को देखें जिनमें द्वारा विमर्श अपूर्त, उत्पादनको को बढ़ाना तथा उत्पादन विस्तृत की सही स्थान पर सुरक्षापूर्ण वितरण सम्बन्धित होगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद की 45वीं बैठक :-
राष्ट्रीय विकास परिषद की 45वीं बैठक 18 सितम्बर 1993 को पारिषदाधिकारी महावर एनकैस के प्रधानमंत्री श्री पीयूष नरसिंहसाराव की आयोजना में सम्पन्न हुई।

(1) Summary Record of Discussion of the National Development Council(N.D.C.) meeting Vol V (45th to 50th meetings) Govt. of India, Planning commission P-26.
(2) National Development Committee on Power-I bid.
38.9 उपाध्यक्ष योजना आयोग द्वारा उन सुझावों को घोषित किया गया जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किये गये।

राष्ट्रीय विकास परिषद उन सुझावों का सराहा जो राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समितियाँ द्वारा निर्धारित किये गये।

राष्ट्रीय विकास परिषद की उप-समितियाँ द्वारा निर्धारित विषय :-

(क) जनसंख्या
(ख) साकारता
(ग) रोजगार
(घ) सूचन स्तर पर योजनाएं तथा उनमें आम व्यक्ति की सहभागिता।

यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मुख्यमंत्रियों को इन विनुओं पर और अधिक विचार किये करना चाहिए तथा जनसंख्या सम्बन्धी विषय को लागू करने के लिए उन्हें संचालन मुद्दों को लागू करने का निर्देश दिया गया।

37.1 यह निर्णय भी लिया गया कि इन सभी मुद्दों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा जिनमें राजनीतिक नेता तथा व्यापार संघ (Trade Union) के लोग भी उपस्थित हैं तथा कार्यवाही राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्देशानुसार ही की जायेगी।

37.2 समिति द्वारा उन सभी प्रमाणार्थी योजनाओं के हस्ताक्षर (केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं का राज्य का हस्ताक्षर) को राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्देशानुसार संचालित किया जायेगा जो दिसंबर 1991 में जारी किये गये थे।

आठवीं पंचवर्षिकौ योजना (1992–97)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से आयोजना हमारी नीति स्तम्भों में से एक रही है तथा हमारी वर्तमान शक्ति उसकी उपलब्धियों की देन है। आजकल यह एक मान्यता है कि क्रिया कलाप के कई क्षेत्रों में विकास को अनावश्यक नियंत्रण से तथा बिन्यमों तथा राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त करके ही सर्वत्र स्वतंत्र रूप में सृजित किया जा सकता है। साथ ही हमारा विश्वास है कि देश की संस्कृति तथा विकास को पूर्णता प्राप्त बाजार व्यवस्था पर नहीं।

(5) Transfer of Centrally sponsored Schemes (CSS) to the State in pursuance of the NDC’s decision taken in Dec. 1991.
छोड़ा जा सकता है। क्रयशक्ति समर्थित “मांग” तथा “पूर्ति” के बीच संतुलन लाने की
अपेक्षा बाजार से की जा सकती है। किन्तु बाजार “आवश्यकता” तथा “पूर्ति” के बीच
संतुलन सुनिश्चित नहीं कर सकता है। बाजार व्यवस्था की ऐसी कमियों कोदूर करने के
लिए आयोजना आवश्यक है। दृढ़—आर्थिक प्रबन्धन के लिए गरीबों तथा दरिद्रों का ध्यान
रखने के लिए (जो अधिकांश: बाजार व्यवस्था से बाहर हैं तथा जिनके पास बहुत कम
परिस्थितियाँ हैं), आयोजना आवश्यक है। इस प्रकार यह बाजार व्यवस्था तथा आयोजना में
से किसी एक का चयन करने का प्रश्न नहीं है वरन् दोनों में प्रभावी रूप में संबंध स्थापित
kरने की चुनौती है ताकि वे एक दूसरे की पूरक हो सकें।

सर्वार्थीम नामक आठवीं पंचवर्षीय योजना का चरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की
प्राप्ति हेतु आठवीं योजना शाखाओं के अत्यंत तक बेरोज़गारी को प्रायः समाप्त करने के लिए
हेतु सर्वार्थीम अवसर प्रदान करने, जनसंख्याओं के अधिक तथा अधिक वृद्धि पर
निर्भर, आर्थिक शिक्षा का सारस्वतिकण, निर्धारित उन्मूलन, सभी के लिए सुरक्षित
व्यवस्थन तथा आर्थिक व्यवस्थन सुविधाओं की व्यवस्था, खाद्याण्व में आस निर्माण तथा
उसके नियांत एवं अभिवृद्धि के लिए कृषि विकास तथा विकिशोधन की आर्थिकता देती है।

सर्वकार ने भारतीय उद्योग को प्रतिस्पृधीतबक प्रोत्साहन देने के लिए बहुत
मुद्‍दे दिए हैं। आठवीं योजना इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है और आर्थिक
विकास के लिए अपने पहले पर अधिक बल देती है सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन केंद्र
क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा जैसे सामाजिक महत्व वाले, उच्च प्रौढ़ों की तथा आवश्यक
अधिस्थतिक संरचनाएं सार्वजनिक क्षेत्रों सुधार तथा गतिशील बनाने के लिए उसकी
संस्थाओं का समुचित निदान किया जायेगा। तवरित आर्थिक तथा आर्थिक विकास के
लिए उपयुक्त वातावरण बनाने हेतु भौतिक आधारमूल संरचनाओं का सुधारकरण विशेषतः
ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई के क्षेत्र में आठवीं योजना के मुख्य केंद्र बिंदु थे।

विकास कार्यक्रमों की सफलता कई गुण इसकी हो सकती है यदि लोग कार्यवाहन
में पूरे मन से भाग लें। अतः आठवीं योजना के लिए अनुकूल कार्यान्वयन कार्यनीति जन
संस्थाओं के निर्माण तथा सुधारकरण और लोगों की सत्क्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है।
सर्वकार की मूल्यवादिक विकास के कार्यों में लोगों की भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करने
की होगी।
आठवी योजना में सकल घरेलू उत्पाद के लिए 5.6 प्रतिशत की औसत विकास दर की व्यवस्था की गई है। इसका वित्तीयों अविकल्कर घरेलू संसाधनों से किया जायगा, योजना के उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनुकूलन एकक्रम व्यवहार (मैको) आर्थिक नीतियों के साथ-साथ केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक व निजी उद्योगों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय अनुशंसन का पालन भी आवश्यक होगा। योजनावाद विकास में सभी सामाजिक सहयोगियों सरकार, कृषि, ट्रेड यूनियन, व्यापार आदि के मद्देख सर्वसम्मति तथा लाभप्रद सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार योजना राष्ट्रीय विकास का एक संयुक्त प्रयास है।

एक उच्च केंद्रीकृत आयोजना प्रणाली से दिशापर्वत आयोजना की ओर हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। दिशापर्वत आयोजना के माध्यम से सरकारी नीति में किसी परिवर्तन का समय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की स्पष्टता से प्रस्तुत करना सम्भव होगा।

चित्रलेश चारीस वर्षों में विकास के लिए योजना बनाने के अन्य अनुभव की पूछताछ में तथा परिवर्तन की प्रभाव आर्थिक परिवर्तन के तहत जीता कि वे अब उम्मीद कर आई हैं। यह प्रस्ताव पूर्ण विकल्प अनुचित हो गया है कि भविष्य में आयोजना की भूमिका व्या होगी। इस प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए यह देखा होगा कि भारत में योजना निर्माण का स्वरूप व्या रहा है और भविष्य में हम आयोजना से क्या उम्मीद करते हैं?

जब प्रथम रंगविशेष योजना में योजना सम्बन्धी प्रलेखों में पहली बार "आयोजना" शब्द को शासकीय तौर पर परिभाषित किया गया तब इससे से प्रभावित किया गया शब्द 'लोकतात्त्विक आयोजना' था। जो 'नियुक्त' पर आवश्यक योजना से विलिकृत भिन्न था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिष्ठा प्रकार की केंद्रीकृत आयोजना भारत में कमी नहीं थी। व्यवहार में बाजार अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख खंड में आवंतन की राशि निर्भर थी। हैं सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तार्थ ने राष्ट्र के आर्थिक जीवन को बढ़त दूर तक प्रभावित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की लागत निरुपेक्षता, लक्ष्यों को प्राप्त करने में बढ़ती हुई अर्थपूर्णता और उसके संसाधनों के इस्तेमाल, जिसकी वजह से उच्च लागत जीवन लिए बिना अपने कार्यकलापों को चालू करा नहीं उसकी भूमिका को परिभाषित और सीमित करने तथा उसके कार्य के उद्देश्यपर्क सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए

41. प्राकृतिक प्रकाशीय योजना खंड 1 भारत सरकार योजना आयोग नहीं दिखी
42. वही प्रत्याहार पृष्ठ - 1
भज्जूर कर दिया। परिणामस्वरूप योजना आयोग की भूमिका को पुनः परिवर्तित करने की आवश्यकता है। मानवीय तथा आर्थिक विकास के 'इंटर सेंक्टेल' क्षेत्र में नीति निर्देश के लिए समुचित वृद्धिकोण विकसित करने में आयोग को एकीकृत भूमिका अदा करनी है। सामाजिक क्षेत्रों में, समानित नीति निर्माण के लिए स्कीमों का प्रभावी बनाना है। एजेंसियों की मौजूदा विविधता केवल हानिकारक ही नहीं है बल्कि लम्बी आवश्यक प्रक्रियाओं के कारण प्रतिकूल उत्पादी है। एकीकृत वृद्धिकोण से कम लागतों पर बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

अबतक संसाधन आवंटन में योजना आयोग की मुख्य भूमिका रही है इसे पदलना होगा। केवल योजना परियोजनाओं में वृद्धि पर ध्यान देने के बजाय, हमें आवंटनों के उपयोग की क्षमता में वृद्धि तथा निश्चित प्रावश्चिक क्षमता की समानान्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। योजना आयोग को राज्यों तथा केन्द्रीय-केन्द्रीय मन्त्रालयों के बीच महत्वपूर्ण कार्य करने व व्यवस्थापन करने की भूमिका निभानी है, जिससे सहज परिवर्तन लाता जा सके तथा वित्तीय अनुशासन की संरक्षण से बन सके। लक्ष्यों के स्थापन निर्धारण तथा स्कीमों की प्राथमिकता के जरिए समाचार वृद्धि की दिशा का उठाव करके, गत्त्वार्थों को कम करने के प्रयास किये जायेंगे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गयी:
(i) शताब्दी के अंत तक तकनीक संयुक्त घरों के स्तर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना।
(ii) लोगों की सक्षम भागीदारी तथा प्रोत्साहित की एवं गैर प्रोत्साहित की प्रभावी स्कीम के जरिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण।
(iii) प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकवाद तथा 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के बीच निकायों का पूर्ण रूप से उन्मूलन।
(iv) अर्थव्यवस्था सहित सभी गाँव एवं संस्कृत सम्पदा के लिए सुलभ, सुरक्षित रूप से नियंत्रित प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रवाहण एवं सिर पर मल ढोने की प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन।
(v) खाद्यान्त में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा निर्यात के लिए और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए वृद्धि संबंधित तथा विशिष्टता प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

43. प्राप्तबन्ध : आठवीं पंचवर्षीय योजना खंड 1 - मानव सशक्त योजना आयोग नई दिल्ली पृष्ठ सं°-19-20 122
योजना आयोग ने अब संस्थागत कार्यनिषिद्धताएँ तैयार की हैं जिसका अभिप्राय जिला, 
लाइक तथा ग्राम स्तर तक विभिन्न लोक संस्थाओं को सृजित या सुधार करना है 
जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं से इन कार्यक्रमों को जोड़कर निवेश स्तर पर 
लाने का अनुकूलतम बनाने के साथ केंद्रीय योजना में परिप्रेक्ष्य निवेश उद्देश्यों 
को समावेशित विकास जा सके। लोगों द्वारा बुनी हुई पंचायतों तथा नगर पालिकाओं 
को अपने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को तैयार करने तथा कार्यान्वयन में और 
अधिक भूमिका निभाने होगी। उनमें पर्यावरण वित्तीय संसाधन, तकनीकी प्रबंध 
सम्मेलन इनपुट तथा निर्माण लेने का प्राथमिक निर्धारित करना होगा। 
स्वच्छ-सुस्फोक ऐसे सिस्टमों तथा अन्य लोक संस्थाओं की भागीदारी ग्रामीण मोतीको स्तरीय सहभागिता 
आयोजना के लिए अनिवार्य है।

परिवर्तन, आधुनिकीकरण तथा समायोजन के लिए संभावना झिंक यह एक लघीली 
योजना है। परिवर्तन जो राज्यों तथा वर्तमान केंद्रीय मंत्रालयों के लिए प्रतिबंधित किया 
गया है। इसमें संसाधनों का पर्याप्त रूप में काफी बढ़ा घटक है, जिसे राज्यों तथा 
केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा भी जुटाना है।

यह योजना निष्पादन मुक्त है। यह अपनी आवंटनकारी भूमिका पर बल न देकर 
आयोगों का अनुकूलतम रूप में उपयोग कैसे किया जाए, पर जोर देती है। इसमें 
निष्पादन सुधार, गुणवत्ता, चेतावनी, प्रतिस्पर्धा, प्रशासन-दक्षता तथा समय पर 
परियोजनाओं को पूर्ण करने पर जोर दिया गया है। अतः निष्पादन के लिए प्रतिस्पर्धा 
देने तथा प्रशासनमुद्दाएँ निम्नलिखित बनाने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहयोग के फायदे 
को उपयुक्त रूप में संवीदित किया गया है।

आठवी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। यदि 
लोगों को कमाने के पर्याप्त अवसर मिलें जहाँ वे रहते हैं तो वे शहरी क्षेत्रों में 
पलायन नहीं करेंगे। ऐसे रोजगार अवसरों के विस्तार के लिए रोजगार को राहत 
रूप से सृजित करने के बदले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी उत्पादनकारी परिसंभवति 
निर्माण करके ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इन 
परिसंभवतियों से उत्पादकता में वृद्धि तथा और अधिक काम करने के अवसर पैदा 

46. प्राकृम्य : आठवी प्रकार की योजना खंड 1 भारत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली पुस्तक सं-2
हो सकते हैं। जिससे निरंतर विकास होता रहेगा। आठवीं योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को किए गए आवंटनों पर कृषि प्रदेश करने से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रीय ने कुल बजट वाहित निर्देश प्रदान का लगभग 81.7 प्रतिशत सामान्य, आधारित संरचना तथा कृषि क्षेत्रों को गया है। पर सातवीं योजना में 70 प्रतिशत की तुलना में है।

केंद्रीय कार्यक्रमों सहित राज्यों का कुल योजना परियोजना का निर्माण करेगा। राज्य योजनाओं के लिए कुल बजट वाहित 80 78500 करोड़ होगी। जिसमें गामत्व केंद्रीय सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों और योजना राजस्व कार्यालय अनुदान बहुत मुकाबले केंद्रीय सहायता शामिल है। हमने अब राज्यों के लिए जो प्राक्कान कर्ता है वह सातवीं योजना के दो चुने से कुछ अधिक है।

कुल निवेश के अनुसार - 1 अर्धेव वक्ता के कृषि क्षेत्र का निवेश घट रहा है। भूमि की सीमित उपलब्धि जिसके लिए गैर कृषि की मांग भी बढ़ रही है के द्वारा के क्षेत्र कृषि की वृद्धि जारी रखनी होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि पर है। हमें इस तथ्य को भी नहीं नकारना चाहिये कि रोजगार का दो संभावित भाग कृषि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और हमारे निर्मल आय का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से आता है। इसलिये कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में निजी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयोगों द्वारा सुजित किए गए एक अच्छे आधारभूत संरचना का पूर्वभूमि में ही फल फूल सकता है। कृषि में विकास की मुख्य जानकारी राज्यों की है और कृषि तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न करने होंगे। इस प्रकार उन पूरी तरह के राज्यों को और विशेष ध्यान दिलाना चाहिए जिन्हें अनुशासन के लाभ नहीं मिल पाये हैं।

47. प्राक्कान : आठवीं पद्धतीय योजना खंड 1 भारत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली प्रसाद पृष्ठ सं-4
हो सकते हैं। जिससे समय बिकास होता रहेगा। आठवीं योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को किए गए राष्ट्रीयों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों को कुल बजट की सहायता का लगभग 81.7 प्रतिशत सामाजिक, आधारित संचार जैसे कृषि क्षेत्रों को जाता है। पर सातवीं योजना में 70 प्रतिशत की तुलना में है।

केंद्रीय कार्यालयों सहित राज्यों का कुल योजना परियोजना ₹ 179985 करोड़ होगा। राज्य योजनाओं के लिए कुल बजटीय सहायता ₹ 78500 करोड़ होगी। जिसमें नागरिक केंद्रीय सहायता, नियोजन सहायता, प्रावधान कार्यक्रमों को योजना राजस्व धारा नुस्खा के मुकाबले केंद्रीय सहायता शामिल है। हमने अब राज्यों के लिए जो प्रायस्थन क्षेत्र है वह सातवीं योजना के दो घटकों से कुछ अधिक है।

कुल निवेश के अनुपात में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र पर निवेश घट रहा है। भूमि की सीमित उपलब्धता जिसके लिए गैर कृषि की मांग भी बढ़ रही हैं के द्वारा के जीवन कृषि की वृद्धि जारी रखनी होगी। बड़ी हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि पर है। हमें इस तथ्य को भी नहीं नकारा चाहिए कि रोजगार का दो तौर पर वजह कृषि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और हमारे निर्यात आय का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से आता है। इसलिये कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में निजी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयासों द्वारा सुझाव दिए गए एक अच्छे आभासमूह संचार का पूर्वभूमि में ही फल फूल सकता है। कृषि में बिकास की मुख्य लेखांकनीय राज्यों की है और कृषि तथा ग्रामीण आधारभूत संचार के बिकास की दिशा में अधिक प्रयास करने होंगे। इस संदर्भ में उन पूर्व क्षेत्र के राज्यों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहिए जिन्हें अभी तक हरित क्रान्ति के लाभ नहीं मिल पाये हैं।

47. प्राक्कल्पना : आठवीं योजना खंड १, भारत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली प्रसारण पृष्ठ 36–4
1992–97 आठवीं योजना के दौरान रोजगार संबंधित तथा दी गयी क्षेत्रीय मूल्य सहायता प्रतिशत\(^*\)

<table>
<thead>
<tr>
<th>सं</th>
<th>सेक्टर</th>
<th>क्षेत्रीय संबंधित वार्षिक मूल्य</th>
<th>रोजगार प्रत्यास्थता 1977–78 से 1983</th>
<th>रोजगार संबंधित उपलब्ध 1983 से 1987–88</th>
<th>आठवीं क्षेत्रीय योजना के लिए लक्ष्य</th>
<th>6–7 काल में के अनुसार प्रयोग की गयी प्रत्यक्षितता</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>कृषि</td>
<td>3.1</td>
<td>0.49</td>
<td>0.36</td>
<td>0.50</td>
<td>1.6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>खान व खादन</td>
<td>8.0</td>
<td>0.67</td>
<td>0.85</td>
<td>0.85</td>
<td>6.8</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>निर्माण</td>
<td>7.3</td>
<td>0.68</td>
<td>0.26</td>
<td>0.50</td>
<td>3.7</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>निर्माण</td>
<td>4.7</td>
<td>1.00</td>
<td>1.00</td>
<td>1.00</td>
<td>4.7</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>विज्ञान</td>
<td>7.8</td>
<td>0.74</td>
<td>0.48</td>
<td>0.50</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>परिवहन व संचार</td>
<td>6.6</td>
<td>0.92</td>
<td>0.35</td>
<td>0.60</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>सामाजिक सेवाएं</td>
<td>6.0</td>
<td>0.99</td>
<td>0.42</td>
<td>0.70</td>
<td>4.2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>योग</td>
<td>5.6</td>
<td>0.58</td>
<td>0.31</td>
<td>0.47</td>
<td>2.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*प्राकृतिक : आठवीं पचवीं योजना खंड 1 भारत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली पृष्ठ संद-60
आदर्श योजना (1992–97) विकास के वृहद शीर्षों द्वारा सर्वजनिक क्षेत्रक परिवर्य
केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र

<table>
<thead>
<tr>
<th>नं</th>
<th>विकास के शीर्ष</th>
<th>वज़तीय सहायता</th>
<th>केन्द्र आई केंबी आर</th>
<th>जोड़रा</th>
<th>राज्य</th>
<th>संघ राज्य क्षेत्र</th>
<th>जोड़रा</th>
<th>आदर्श योजना का %</th>
<th>सातवी योजना का %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>कृषि तथा सम्बन्धी सेवायें</td>
<td>12394.00</td>
<td>224.00</td>
<td>12618.00</td>
<td>42135.35</td>
<td>239.15</td>
<td>54992.50</td>
<td>12.67</td>
<td>14.27</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>श्रामीण विकास</td>
<td>2417.00</td>
<td>0.00</td>
<td>24170.00</td>
<td>10213.26</td>
<td>42.10</td>
<td>34425.36</td>
<td>7.93</td>
<td>5.01</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>6750.16</td>
<td>0.00</td>
<td>6750.16</td>
<td>1.55</td>
<td>1.75</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>रुझान</td>
<td>13136.00</td>
<td>53859.00</td>
<td>66795.00</td>
<td>47291.58</td>
<td>1474.51</td>
<td>115561.09</td>
<td>26.62</td>
<td>30.48</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>लग्जोग तथा खनिज</td>
<td>9186.00</td>
<td>28353.00</td>
<td>32539.00</td>
<td>9284.89</td>
<td>97.86</td>
<td>46921.75</td>
<td>10.81</td>
<td>12.48</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>सरकारिय</td>
<td>8636.00</td>
<td>32341.00</td>
<td>40977.00</td>
<td>13786.58</td>
<td>1161.99</td>
<td>55925.57</td>
<td>12.88</td>
<td>12.76</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>संगार</td>
<td>715.00</td>
<td>24382.00</td>
<td>25097.00</td>
<td>12.50</td>
<td>0.48</td>
<td>25109.98</td>
<td>57.8</td>
<td>3.60</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी</td>
<td>3739.00</td>
<td>200.00</td>
<td>3939.00</td>
<td>188.72</td>
<td>3.99</td>
<td>4131.71</td>
<td>0.95</td>
<td>1.13</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>परिस्थितिक स्थान प्रयोग</td>
<td>1200.00</td>
<td>0.00</td>
<td>1200.00</td>
<td>3654.16</td>
<td>55.82</td>
<td>4909.98</td>
<td>1.13</td>
<td>1.27</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>सामाजिक आधिकता एवं सामाजिक सेवायें</td>
<td>1040.55</td>
<td>44.00</td>
<td>1084.55</td>
<td>5079.04</td>
<td>196.41</td>
<td>6360.00</td>
<td>1.47</td>
<td>0.94</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>सामाजिक सेवायें</td>
<td>29508.45</td>
<td>4937.00</td>
<td>34445.45</td>
<td>41588.76</td>
<td>2977.69</td>
<td>79011.90</td>
<td>18.20</td>
<td>16.31</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल योजना</td>
<td>103725.00</td>
<td>144140.00</td>
<td>247865.00</td>
<td>179995.00</td>
<td>6250.00</td>
<td>434100.00</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

इसमें समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम के लिए आवंटन शामिल है।

इसमें सिंचाई एवं धार्मिक नियंत्रण शामिल है।

इसमें वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए आवंटन शामिल हैं।

49. प्राकथम: आदर्श विश्वविद्यालय योजना खंड 1 भारत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली वृत्र सं-61
नवी पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद की 47वीं बैठक :-

राष्ट्रीय विकास परिषद की 47वीं बैठक 16 जनवरी 1997 को विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री श्री एस.जी. देवगिरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
38.1 प्रधानमंत्री श्री एस.जी. देवगिरी द्वारा Draft Approach Paper to the Ninth Five Year Plan (1997–2002) पेश किया गया तथा योजना आयोग से यह निवेदन किया कि नवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप उन आह्वानों पर निर्भर होना चाहिये जोकि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में निर्धारित की गई है।
38.3 अनेक मुख्यमंत्रियों ने जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्या को राज्य की मुख्य समस्या बताया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में विश्वास में लेना चाहते थे ताकि उसी विश्वास को आधार रखकर पांचवा वेतन आयोग निर्धारित किया जाये।
38.4 प्रधान मंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों से संसाधन विनियम (Resource Mobilisation) पर विचार करने तथा इस समबंध में अपने राज्य को बेहतर बनाने की अपेक्षा की। जिससे कि नवी पंचवर्षीय योजना के लिए पत्ताक चंदन उपलब्ध हो पायें।
38.5 Un accounted Money के संदर्भ में उद्योगपतियों तथा अर्थशास्त्रीयों से सलाह ली गयी तथा प्रधानमंत्री यह चाहते थे कि कोई भी प्रारूप तैयार होने से पहले यह मुद्दा प्रारंभ मुख्यमंत्री की नजर में आ जाये।
38.6 प्रधानमंत्री द्वारा यह भी इच्छा जाहिर की गयी कि अगला सामान्य बजट 1997–98 का पूर्ण प्रारूप तैयार करने से पहले सभी मुख्यमंत्रियों तथा राजनैतिक पार्टियों को विश्वास में ले लिया जाये।
38.7 प्रधानमंत्री के अनुसार राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिये जो कार्यक्रम बनाये जाते हैं वह तभी सफल होकर राष्ट्र के आर्थिक सुधारकरण में अपनी भूमिका निभा पायेंगे जब इन कार्यक्रमों को लगभग प्रत्येक मुख्यमंत्री तथा राजनैतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त होगा।
38.8 नवी पंचवर्षीय योजना के Approach Paper पर राष्ट्रीय विकास परिषद की सर्वसम्मत राय पर प्रधानमंत्री द्वारा सभी उपस्थित लोगों को घन्यावाद दिया।

50. Summary record of Discussion of NDC meeting Vol. V (April to 50th), Govt. of India, Planning commission P-130.
राष्ट्रीय विकास परिषद की 48 वीं बैठक

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई की अध्यक्षता में प्रातः 10 बजे से 19.02.1999 को राष्ट्रीय विकास परिषद की 48 वीं बैठक विज्ञान मवन में हुई है।

इस बैठक में निम्न मुद्दों पर वार्ता हुई:

1. नवी पंचवर्षीय योजना
2. राष्ट्रीय विकास परिषद की ऊर्जा उप समिति की रिपोर्ट
3. गैंग, चावल, गना, यूरिफा तथा एल्पीफ्लोजी के सहकारी मूल्यों का अवलोकन
4. बढ़ी ग्रामीण निर्माण उन्मूलन कार्यक्रमों के बिता निर्धारण का दायरा तय करना
5. केंद्र निर्धारित योजनाओं का हस्तांतरण।

एक व्यापक विचार-विमर्श के बाद निम्न निर्णय हिसे गये:

1. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो समिति के समक्ष रखा गया था, उसे राष्ट्रीय विकास परिषद की मान्यता मिली।
2. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ऊर्जा पर गठित राष्ट्रीय विकास परिषद की ऊर्जा उपसमिति की सराहना की गयी तथा केंद्र एवं राज्यों से यह गृहारिश की गयी कि वह ऊर्जा उपसमिति के चुनावों को वरीयता से लागू करें।
3. आवश्यक वस्तुओं के सहकारी मूल्य अवलोकन की भी सराहना की गयी तथा यह महसूस किया गया कि किसानों, उपभोक्ताओं तथा समाज के गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य होना चाहिए तथा वित्तीय अनुमोदन, स्वीची नियत्रण तथा अन्य मुद्दों भी नजर आदर्श नहीं होने चाहिए। एक सुन्तुलित तरीका सामने आना चाहिए।
4. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यह निर्धारित किया गया कि एक उप-समिति गठित की जानी चाहिए जिसकी अध्यक्षता योजना आयोग का उपाध्यक्ष करे तथा उस ऊप समिति के अन्य सदस्य केंद्रीय तथा राज्य स्तर के मंत्री हों जोकि बड़ी ग्रामीण निर्माण उन्मूलन कार्यक्रमों के बिता निर्धारण का दायरा तय करें।
5. समिति द्वारा इस बात पर ध्यान दिलाया गया कि केंद्र तथा राज्य मंत्रियों में केंद्र संचालित योजनाओं को लेकर काफी मतभेद हैं। अतः इस मुद्दे पर भी एक उप समिति

51. Minutes of the meeting of the National Development Council held, Under the Chairmanship of the Prime-Minister on February 19, 1999 Circulated vide Planning Commission U.O. No. 0110115199 PC Dated 09.03.1999
52. Summary Record of discussion of the National Development Council Meeting Vol V (45th to 50th) meeting Govt. of India Planning commission P-24.
(6) The Finance Minister informed the NDC that the Governor. RBI has agreed to implement the revised ways and means advances to states from 01.03.99 as against the earlier decision of doing so with effect from 01.04.99. In addition, the R.B.I. would consider allowing the states to roll over outstanding over drafts beyond the end of the current financial year as a short term measure to tide over the financial problems.

(7) The Finance Minister informed the states that the earlier decision of doing so with effect from 01.04.99. In addition, the R.B.I. would consider allowing the states to roll over outstanding drafts beyond the end of the current financial year as a short term measure to tide over the financial problems.

नवी चंद्रवीर्य योजना

यदापि नवी चंद्रवीर्य योजना 1 अप्रैल 1997 से शुरू हुई है तथापि औपचारिक नवी चंद्रवीर्य योजना दस्तावेज को अन्तिम रूप से आवश्यक अनुमोदन दिनी थी 19 फ़रवरी 1999 को ही प्रदान किया गया। दस्तावेज को अन्तिम रूप देने में हुई दो वर्ष की इस देरी से इस बात को लेकर इसकी आलोचना की गई कि इसमें चंद्रवीर्य योजना के मूल्य ही अर्थशास्त्र ही गये हैं। विकास में इस संपत्ति आये हैं जब विभिन्न कारणों से, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, चंद्रवीर्य योजनाओं के समय से प्रस्तुत कर पाना सम्भव नहीं रहा है। वर्ष 1966 और 1969 के मध्य के चार वर्ष, 1979 का वर्ष और 1990 से 1992 की अवधि के दो वर्ष ऐसी अवधि थे और जिन्हें प्रत्येक को 'प्लांट होलीडे घोषित किया गया था। यह विकल्प इस संपत्ति भी उपलब्ध था लेकिन सरकार ने उन विकास कार्यक्रमों को जारी रखा जिनकी पिछली सरकारों द्वारा अभियंता की गई थी तथा जिनका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया था।

इस विकल्प की अधिकतम इस विश्वास के आधार पर की गई थी कि 'प्लांट होलीडे विकासात्मक प्रक्रिया के लिए अभियंता कर है। 'प्लांट होलीडे' का मूल्यांकन अर्थ यह है कि सरकार द्वारा एक समय में एक वर्ष से अधिक के लिए कोई वित्तीय प्रतिबंध नहीं की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप जिन परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि अपेक्षित नहीं है। उन्हें किसी आश्वासन के साथ शुरू नहीं किया जा सकता। इसके
बालावा प्यान होलीडेक के दौरान सरकार की भावी नीति के विषय में अत्यंत अनिश्चितता रहती है जो निजी निवेशकों के लिए भी समस्या पैदा करती है। इन निष्ठाओं को सूचीकर करते हुए उर्वरान्य सरकार ने पिछली सरकार द्वारा निरूपित इस योजना को जारी रखने का सुरक्षित निर्णय लिया है। जिससे कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो यह शासन की सत्ता और विकास कार्यनीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जिसका राष्ट्रीय विकास अनुमोदन में शामिल किया गया है। एवं विकास का कार्य करने में निरंतर योजना की अनुमति नहीं। दो जानकारी चाहिए। हमें विचार से यह निर्णय योजना में और योजना के प्रति इस सरकार के विषय के विषय और प्रतिबद्धता के अवधि अभिप्रेरित है।

तथापि प्रत्येक सरकार के पास राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्वाचित व्यापक उद्देश्यों के अन्तर्गत प्राथमिकता के क्षेत्रों के निर्धारण का अधिकार है। शासन के राष्ट्रीय एजेंसिया में इस सरकार ने भी कुछ क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें यह महत्त्वपूर्ण समझती है। इसके परिणामस्वरूप योजना में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया गया है:

(क) प्राथमिक शिक्षा
(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य
(ग) कृषि
(घ) जनसंसाधन
(ङ) सूचना एवं प्रौद्योगिकी

उपरोक्त क्षेत्रों में विशेष कार्य योजनाओं निरूपित की गई हैं, जिनमें क्रियान्वयन के लिए व्यवहारी समयभर कार्यरत्र है तथा जिनमें पर्यावरण उद्धवत्व विश्वसनीय सरासरी भी प्रवाह होने ऐसे दृष्टिकोण की अभिव्यक्तिन है जिसे सुनिश्चित करने के लिए की गई है जिसे कि सही के इन विशेष क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाया जिससे जनसाधारण में अपेक्षित लाभ पहुंच सके।

योजना के अनुमोदन में हुई देश के दूसरे प्रभाव भी हैं वर्ष 1996-97 में जब योजना निरूपण से सम्बंधित विशाल कार्य किया जा रहा था, अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित तेजी आ रही थी। उस समय उच्च आश्रय बनी थीं ऐसा शायद अवस्थित रूप से छूटे हुये।

53. नीति एवं परीक्षण योजना (1997-2002) करण्ड 1 विकास लघु कार्यनीति और नीतियों में स्वातंत्र्य सरकार योजना आयोग में दिल्ली पुस्तक 1
रूप में, तथा 7 प्रतिशत प्रतिवर्षिक से कम जी0डी0पी0 की वृद्धि दर का लघु अकालपनिक
लग रहा था इसके परिणाम स्वरूप जनवरी 1997 में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण
पत्र का अनुमोदन करते समय राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना आयोग को निर्देश दिया
था कि वह नौवीं योजना अवधि के दौरान सात प्रतिष्ठात की औसत वृद्धि दर को बनाए
रखने के लिए एक कार्यनीति बनायें। बहरहाल एक घटनाओं से वृद्धि प्रतिवर्ष भी राष्ट्रीय विकास परिषद में निर्माण लिया कि योजना अवधि के तीन
वष्णु के लिए प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की औसत का प्रयोग करते हुये, योजना के लिये संबंधों
दर को 6.5 प्रतिशत तक संबंघित किया जाना चाहिए, जो शीर्ष स्तर पर योजना के
अंतर्गत प्रस्तुत अपेक्षित नीतिगत परिवर्तनों को अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

योजना की दूसरी अहिंसी विशेषता देश की बढ़ती हुई आर्थिक परिस्थितियों
की पहचान है विषय में विश्वसनीय एवं यी थी कि सभी पूर्व योजनाएं इस दृष्टिकोण पर
आधारित थी कि भारत में आर्थिक विकास प्रमुखतः अर्थ्यवस्था में निवेश अथवा संसाधनों
की उपलब्धता से प्रतिवर्षित है और उच्च विकास दर ऐसे संसाधनों में वृद्धि के माध्यम से
संबंध कर सकती है। नौवीं योजना में रखा गया है कि वर्तमान में देश में आर्थिक
वृद्धि और विकास की समस्या न केवल निवेश के लिए कुल संसाधनों की उपलब्धता है
बल्कि प्रभावी रूप से और कुशलतापूर्वक इन संसाधनों को समावेश करने के लिए आर्थिक
प्रणाली की योग्यता भी है। इताः उपलब्ध संसाधनों के33 समावेश और परिनिर्माण में
सुधार के उपाय करके वृद्धि दर को दौड़ाना संबंध है इस विषय से समझित कई
आयाम हैं जिनका योजना में उल्लेख किया गया है।

प्रेरणा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो देश में निवेश के स्तर को धीमा कर
सकता है, सामाजिक और आर्थिक आवाग संसर्ग उपलब्धता और उन तक पहुंच है, विश्व
के वर्षों में निवेश गोष्ठ संसर्ग तक तारामंडल पहुंच का महत्वपूर्ण समस्या नहीं समझा
जाता था तथापि, वर्तमान में केंद्र और लगभग सभी राज्य सरकारों के बजट पर बहुत
दबाव हैं इसलिए उन्हें वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और समस्तियों जैसे अपने चालू
खर्चों को पूरा करने के लिए भी उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। परिणाम स्वरूप
निवेश है अनुग्रहित निर्देशियों अप्रयात हैं जो अर्थ्यवस्था के विकास के लिए अनिवार्य है। सरकारी

33: नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) खण्ड १ विकास लघु कार्यनीति और नीतियों भारत सरकार योजना आयोग नई
दिल्ली पृष्ठ 2
किता पर दबाव से गस्ती हो गये हैं कि देश में कुल निवेश में सार्वजनिक निवेश का हिस्सा जो आठवी योजना के दौरान 46 प्रतिशत के लगभग होना लक्षित था, आठवी पंचवर्षिक योजना के अंतिम वर्षों में 30 प्रतिशत से भी कम हो गया है।

इससे समझदें: बहुत अधिक अन्तर नहीं आयेगा। यदि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के समावेश के लिए निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि की आशा की जा सके और उससे सार्वजनिक निवेश के घटे हुये हिस्से की प्रतिपूर्ति हो सके। बहरहाल निजी निवेश के उच्च और सतत स्तरों के लिए विशेष रूप से अवसर के उन क्षेत्रों में जो निजी सार्वजनिक निवेश अपयात हैं प्रेक्षक बनाया जाना चाहिये। योजना के तीन भुमिकाओं के क्षेत्रों की पहचान की है।

पहला राष्ट्रीय उत्पादक कार्यकलापों के लिए आधार संरचना की पर्याप्त उपलब्धता अपेक्षित है। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में आधिकारिक आधार संरचना की स्थिति जीवितीयके की तौर पर वृद्धि में सहायता के लिए अवसर है यदि निजी निवेश के माध्यम से आधार संरचना का उपलब्धता में वृद्धि के लिए प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। अपेक्षित नीतिगत ढांचे को अपनी पूर्ण स्थान दिया जाना है।

परिणामस्वरूप लघु अर्थव्यवस्था में समय निजी निवेश आधार संरचना में सार्वजनिक निवेश पर और माध्यम अवधि में आधार संरचना में निजी भागीदारी के लिए आकर्षक से वातावरण निर्माण में उपलब्ध सकलता और उसपर हुई अवसरों से लाभ प्राप्त करने में निजी निवेश की प्रतिकृतिया पर निर्भर होगा।

दूसरा कोई भी निजी निवेश अपयात कुल मांग की स्थिति में निवेश का इच्छुक नहीं होगा। इस बात को चिंतित करने दो वर्षों के दौरान कुछ बल सहित महसूस किया गया है। अत: बचत के समय स्तरों अर्थव्यवस्था में निवेशकों की दर पर संख्या न करते हुये अर्थव्यवस्था में कुल मांग के उच्च स्तरों के सृजन और निरसन रखने पर ध्यान दिया जाना है।

यदि निजी निवेश जो कुल मांग के प्रमुख पहचान के एक है वित्तीय सिद्धांत से निकाला है दूसरे घटकों का अधिक सहायता लेना होगा। विशेष रूप से निर्माण की तीव्र वृद्धि पर। निर्माण की सतत वृद्धि न केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति से निर्भर होती है जो उद्योगी व्यवहार की प्रभावशाली रूप से प्रभावित करती है। अत: यह सुनिश्चित करना 54.

54. निीमे पांचवर्षिक योजना (1997-2002) खंड़ 1 विकास सम्बन्धी कार्यक्षेत्र और नीतियों भारत सरकार योजना अध्याय वह तिल्या पृष्ठ 3.
आवश्यक है कि हमारी नीति अर्थव्यवस्था में कोई भी नियतिरोधी पूर्वग्रह न हो इसे हमारे भविष्य की कार्यवृत्ति का प्रमुख घटक होना चाहिए।

तीसरा कारक जो देश में निजी निवेश मांग को धीमा कर सकता है वह है वित्तीय क्षेत्र की वर्तमान स्थिति। यह महसूस किया जा रहा है कि घरेलू बचतों के रूप में निवेश योग संसाधनों की पर्याप्त होशुलक्ता और वित्तीय पूंजी प्रवाह होने पर भी वास्तविक उत्पादन निवेश के अर्थ में इन संसाधनों को गतिशील बनाना अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिति कार्यकलाप की कुरालता द्वारा प्रभावित होगा। हालाँकि निजी निवेश पर अधिक निर्मिति के साथ एक अच्छा अल्पकालिक वित्तीय स्थिति निर्माण के लिए बाधा हो सकती है। हाल के वर्षों में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के क्षेत्र में की गई अच्छी प्रगति के बावजूद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र को और अधिक एफीक्ट्स किए जाने की आवश्यकता है, जिससे वह उन अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सके। जो इसके समक्ष भविष्य में उपस्थित होंगी। वैदिक अव संस्कृत तथा भारतीय उद्योगों में निजी निवेश जिसे निदेशों की दीर्घवर्षीय प्रतिबद्धता अपेक्षित है में तेजी आने लगी है। अतः दीर्घवर्षीय वित्त के क्षेत्र एवं पद्धतियों विकसित की जानी होगी।

योजना में उपयुक्त तीन कारकों पर दिया गया बल, योजना आयोग द्वारा इनके दृष्टिकोण में एक और निजी निवेश की प्रधानता और दूसरी ओर निजी निवेश पर पर्याप्त निर्माण की प्रणाली से एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आयोजना, जिसमें निजी निवेश की एक अधिक बाजारोमुखीः दौड़े के नीति वही नूतन को और पूर्व-अधिमुखीकरण में किए गए प्रयासों को इंगित करता है। हालांकि निकट भविष्य में, हाल ही के मिले कुछ समय में सर्वजनिक निवेश में आई गिरावट को रोकने के लिए बाइलाइंक नहीं देता। यह केंद्र और राज्य सरकारों की राजकीय समस्याओं के युद्ध स्तर पर समाधान के लिए हासिल हो सकता है। राजकीय समायोजन के लिए कठोर निर्णय लेने और इसहै नौवीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से योग्य किया गया है।

राजस्व वृद्धि करना स्पष्ट रूप से पहला कार्य है जैसा कि योजना में निर्देश किया गया है। हैमें भी भी कई राजस्व श्रेणियों में मात्रा में तेजस्वी करने हैं और इसकी व्याख्या करना आवश्यक है। तथापि एक महत्वपूर्ण युद्ध जिसका उल्लेख किये जाने की

55. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) खण्ड 1 विकास लक्ष्य कार्यनीति और नीतित्व भारत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली पुंथ 4
जरूरत है यह है लगतार गंगीर होती जा रही अन्तर्राजिय जरूरत फ्राइंड्स के हानिकारक प्रभाव। हमारे लिए यह अवस्था है कि हम कर पढ़तियों को इस तरह से संगठन बनाएं कि वह केंद्र व राज्यों में हम सभी को लाभ पहुंचवायें। तुलसी बात जिन पर बत दिये जाने की जरूरत है यह है देश के विभिन्न राज्यों में राजकोशीय प्रयास के स्तर में व्यापक निर्देश लगाने का होना। प्रथम राज्य को अपने कर निर्देश देने को देश के बेहतरीन निर्देशावली राज्यों की तुलना में तलाशने करने की आवश्यकता है जिससे संरक्षण पर समय बन्द करना सुनिश्चित किया जा सके एवं कर प्रशासन को और अधिक कुशल बनाया जा सके। कर राजस्व के अतिरिक्त प्रयोगता प्रभाव अल्पता महत्वपूर्ण हैं। हम विस्तृत एवं संचारी के लिए कम शुल्क वसूल कर इन पर इतनी बढ़ी हानियों नहीं सह सकते हैं। इन सब उपायों के बावजूद जब तक कि हम अपने गैर विकासात्मक व्ययों को न सोकते हमारे विकासात्मक संसाधनों तक पूर्वत मुद्दा होने की सम्भावना नहीं है।

नौदी कंचवासी योजना के वृत्तिकोष प्रति में जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। पर्यावरण उत्पादक रोजगार के सृजन और निर्देशना उन्मूलन के उद्देश्य से वृद्धि और ग्रामीण विकास रिसर्च कीमतों के साथ अर्थ व्यवस्था की संपूर्ण दर को तेज करने सभी के लिए विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए खात और पानु पुर्न चुनिन्दा करने, सुरक्षित जेठन, वहानिक विस्तार देख-रेख की सुविधाएं, सर्वसाइल हांग व्यवस्थित रूप से, आवास और एक समयभूत तरीके से सभी के लिए संयोजकता की बुनियादी से ग्राम प्रादर्श करने, मनसाध्य की वृद्धि दर की नियंत्रित करने सामाजिक गतिशीलता और सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी के जरिये विकास प्रक्रिया की पर्यावरणात्मक विभाजन सुनिश्चित करने, बिजनेस और सामाजिक सूची से सुनिश्चित करने, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्याकार को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के अंतर्गत, एक एक के रूप में समाज बनाने लोगों की सहभागी संसाधनों जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं सहकारिताओं और व्यवसाय समुदाय संस्थाओं के विकास और प्रशासन और आयामित्व के विभेद के लिए विभागों को सुदृढ़ करने पर उच्च वाणिज्यिकता प्रादर्श की गई है। यही प्रथमकार्य नौदी कंचवासी योजना के उद्देश्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथानिर्देशित योजना के संबंध में उद्देश्य के भीतर कुछ

58. नौदी कंचवासी योजना (1997-2002) लघु 1 विकास लघु वाणिज्यित और नौदी कंचवासी भारत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली पुस्तिका 5

135
विशिष्ट क्षेत्रों को विशेष बल देने के लिए चुना गया है। इन क्षेत्रों के वास्ते विशेष कार्यवाही योजनाएँ (एसएचएचपी) तैयार की गई है ताकि पर्याप्त संसाधनों के साथ कार्यवाही योग्य और समयबाध्त लक्ष्यों की योजना की जा सके। समास्थान: विशेष कार्यवाही योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक और भौतिक आधारस्तुत ढांचा कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और जल नीति के विशिष्ट पहलू समाजित है।

नौवी पंचवर्षीय योजना को हमारी विशेष विकास कार्य नीति की सुधारता और साथ ही इसकी कमजोरियों पर साक्षात्तीय पूर्वक विचार करते हुये आधारित किया गया है तथा इसके अंतर्गत देश के सामाजिक का विकास को समृद्धित दिशा-निर्देश प्रदान करने और संपूर्ण बनाए रखने तथा प्रवास किया गया है। नौवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास के नये युग में प्रवेश करना होगा, जिसमें न केवल केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा सभी लोग विशेष रूप से जोशी लोग एक सहभागी योजना प्रक्रिया के भागी दान नहीं सकें। ऐसी विकास नीतियों से जनता और निजी क्षेत्रों तथा सरकार के सभी विभागों की सहभागिता, न्याय और समानता के साथ विकास सुनिश्चित करने के वास्ते महत्वपूर्ण है।

नौवी पंचवर्षीय योजना में तीन आधिक विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच अनेक कदमों को महत्व दिया गया है। इसमें ऐसी नीतियों को अपने अंतिम उद्देश्य के अनुसार के साथ जो गरीबों नुकह हैं और जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं के दूर करना है। उच्च विकास नीतियों में तालमेल बिठाने की आवश्यकता को भी स्वीकारा गया है। इस प्रकार नौवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को निम्न प्रकार बताया जा सकता है।

‘सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास’

नौवी पंचवर्षीय योजना के विशिष्ट उद्देश्य, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित निम्न प्रकार है--

(1) पर्याप्त उठायुक्त रोजगार के सृजन और निर्धारत उन्नति उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि और यामीण विकास का प्राथमिकता।

57. नौवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002) लघुपुत्रों विकास लघु कर्मनीति और नीतियों में भागत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली पुंज 1 58. वही पुस्तक संख्या–2
(2) सिध्द योजनाओं के साथ अर्थव्यवस्था की विकास दर तेज करना।
(3) सभी के लिए विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
(4) सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, आवास और एक समयबाद्ध तरीके से सभी के लिए संगठनका की बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था करना।
(5) जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करना।
(6) सामाजिक गतिशीलता और सभी स्तरों पर लोगों की सामाजिक तथा भागीदारी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया की पर्यावरणात्मक स्थिरता सुनिश्चित करना।
(7) सिद्धांतों और सामाजिक रूप से असहमति प्राप्त वर्ग सभी के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दर्जे के क्षेत्र में प्रवेश का सामाजिक परिवर्तन और विकास को एजेंटों के साध्यता बनाना।
(8) पंचायती राज संस्थाओं और सहकारिताएं और स्वयं सेवी दल जैसे लोगों की सहमानी संस्थाओं का विकास और प्रोत्साहन।
(9) आत्मनिर्भरता का निर्माण करने के लिए प्रयासों को सुधार करना।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय संसाधन

(1) नौवीं पंचवर्षीय योजना में (1997–2002) 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की जी0.5 हो विकास दर की परिखण्डन की गई है। 1996–97 कीमतों पर सरकारी क्षेत्र योजना परियोजना 8.59,200.00 करोड़ है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना दर्शाता योजना खर्च और अनुपादित योजना परियोजन के अनुसार वाल्टिक दृष्टि से क्रमशः 33 प्रतिशत और 33 प्रतिशत है। केंद्र की योजना तथा राज्यों की योजनाओं का हिस्सा जिसमें संध राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित है क्रमशः 57 प्रतिशत और 43 प्रतिशत होगा।
(2) करोड़ 4.89,361.00 करोड़ के केंद्र के योजना परियोजना का वित्त पोषण क्रमशः 41.70 प्रतिशत और 58.30 प्रतिशत और 58.30 प्रतिशत की सीमा तक सकल जडत साहायता (जी0.5 हो और सी0.5 हो) के आतंकी और बाहुल्य संसाधनों (आई0.5 हो और आई0.5 हो) द्वारा किया जाएगा।

59 नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) खंड 1 विकास खंड कार्यनीति और नीतियों भारत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली पृष्ठ 2-3
(3) चालू राजस्व से शेष (बीसीआरआर०) नकारात्मक रहने की प्रत्याशा है जबकि आठवी योजना में सकारात्मक बीसीआरआर० प्रकटित किया गया था।

(4) योजना अवधि के दौरान कर राजस्व जी०डी०पी० का 10.15 प्रतिशत से 11.50 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जो 10.87 प्रतिशत औसत कर जी०डी०पी० अनुसार होगा।

(5) कर-भिन्न राजस्व जी०डी०पी० का 2.8 प्रतिशत बना रहेगा।

(6) पूर्वनुमान है कि योजना मित्र राजस्व खर्च (एस्पीआईआर) 1997–98 के जी०डी०पी० के 10.05 प्रतिशत से घटकर 2001–02 में 9.5 प्रतिशत रह जाएगा।

(7) उच्च सम्मांत्र केंद्र की योजना के लिये वित्तीय संस्थानों के 80 प्रतिशत का योगदान करेंगे।

(8) उम्मीद की जाती है कि सी०पी०एस०आई० अपने योजना परियोजना का 90 प्रतिशत का वित्त पोषण आई०डी०बी०आर० के माध्यम से करेंगे।

(9) आयोजना अवधि के दौरान राजकीय घाटा जी०डी०पी० का 6.1 प्रतिशत से कम होकर 4.1 प्रतिशत रहने की संभावना है।

(10) राज्यों के द्वारा उच्चर की राशि उनके नीचे पंचवर्षीय योजना परियोजना की 48 प्रतिशत होनी ज़्यादा कि आठवी पंचवर्षीय योजना के पूर्वनुमानों में था।

(11) राज्य स्तरीय उपक्रमों के आंतरिक संसाधन भी योजना परियोजना के 4 प्रतिशत पर अधिक होने की उम्मीद है जबकि आठवी पंचवर्षीय योजना के लिए 2 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था।

(12) राज्यों के बीसीआरआर (अंतरिक्ष संसाधन जुटाने-एसआरएम० प्रतिबद्धता सहित) में

80. नीचे पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दौरान 1 विकास लक्ष्य कार्यक्रम और नीचे राष्ट्रीय सरकार योजना आयोग नहीं, दिल्ली पृष्ठ 193
सुधार होकर ये नौवीं पंचवर्षिय योजना के दौरान सकारात्मक हो जायेंगे।

नौवीं पंचवर्षिय योजना के लिए वित्त पोषण की पद्धति पहले की पद्धति से काफी मिन्न है। यहाँ तक कि घाटे के वित्त पोषण की शून्य स्तर पर रखा गया है और चालू राजस्व खाते का शेष नकारात्मक बन गया है। इसकी वजह से उधारों व अन्य देनदारियों की काफी ऊँची प्रतिशतता की आवश्यकता हुई है।

नौवीं पंचवर्षिय योजना के प्रथम दो वर्षों (1997-98) संसंगृहित अनुमान और 1998-99 के बजट अनुमान के लिए केंद्रीय योजना के वास्तव संकल बजट सहायता नौवीं पंचवर्षिय योजना के लिए ऐसी कुल सहायता का क्रमशः शेष तीन वर्षों के लिए बजटीय सहायता काफी मात्रा में बढ़ानी पड़ेगी तकक नौवीं पंचवर्षिय योजना के लिए प्रभावित केंद्रीय योजना परियोजना की उपलब्धि हो सके। जहाँ तक आई00ई00आर0 का भी सम्भव है, 1997-98 के लिए संसंगृहित अनुमान और 1998-99 के बजट अनुमान योजना अवधि के लिए कुल का क्रमशः लगभग 15.8 प्रतिशत और 19.5 प्रतिशत है। इसलिए प्रभावित योजना परियोजनाओं के वित्त पोषण के उद्देश्य से सी00पी00एस00ई0 का शेष वर्ष में आई00ई00आर0 के उच्च स्तर पुनः बनाने होगी।

केंद्र और राज्यों की वित्त पोषण पद्धति तथा योजना के लिए संकल बजटीय सहायता तथ्यों के वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। राज्यों के स्तर के संसाधनों और केंद्र के बी00सी00आर0 का परिकलन करने में यह कल्पना की गई है कि केंद्र के संकल कर राजस्व का 29 प्रतिशत अपेक्षित संविधान संसंगृहन विशेषक पारित होते।

61. नौवीं पंचवर्षिय योजना (1997-2002) खण्ड 1 विकास अनुमानकार्यनिति और नौवीं भारत सरकार योजना आयोग नई दिल्ली पुस्तक एक्स 194
ही राज्यों को आवश्यक कर दिया जायेगा। किन्तु दसवें किता आयोग का निर्णय केवल 1999–2000 तक वैध रहेगा। संसाधन स्थिति में पर्याप्त परिक्षेत्र हो सकता है, जो राज्यवर्ती किता आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

नवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्षेत्र</th>
<th>केंद्र</th>
<th>प्रतिशत</th>
<th>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</th>
<th>प्रतिशत</th>
<th>कुछ</th>
<th>नौवी योजना</th>
<th>आठवी योजना</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>कृषि एवं निवास</td>
<td>14876</td>
<td>3</td>
<td>27586</td>
<td>7.5</td>
<td>42462</td>
<td>4.9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सिंचाई एवं बाढ़</td>
<td>2291</td>
<td>0.5</td>
<td>53129</td>
<td>14.4</td>
<td>55420</td>
<td>6.5</td>
<td>12.7</td>
</tr>
<tr>
<td>निर्माण</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ग्रामीण विकास</td>
<td>42278</td>
<td>8.6</td>
<td>32408</td>
<td>8.8</td>
<td>74686</td>
<td>8.7</td>
<td>7.9</td>
</tr>
<tr>
<td>विशेष कार्यक्रम</td>
<td>0</td>
<td>0.0</td>
<td>3649</td>
<td>1.0</td>
<td>3649</td>
<td>0.4</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>ऊर्जा</td>
<td>153807</td>
<td>31.4</td>
<td>68568</td>
<td>18.5</td>
<td>222375</td>
<td>25.0</td>
<td>26.6</td>
</tr>
<tr>
<td>उद्योग व खनिज</td>
<td>51664</td>
<td>10.6</td>
<td>13484</td>
<td>3.6</td>
<td>65148</td>
<td>7.6</td>
<td>10.8</td>
</tr>
<tr>
<td>परिवहन</td>
<td>81791</td>
<td>16.7</td>
<td>37582</td>
<td>10.2</td>
<td>119373</td>
<td>13.9</td>
<td>12.9</td>
</tr>
<tr>
<td>संचार</td>
<td>47249</td>
<td>9.7</td>
<td>31</td>
<td>0.0</td>
<td>47280</td>
<td>5.5</td>
<td>5.8</td>
</tr>
<tr>
<td>विज्ञान तथा प्रासंगिक और पर्यावरण</td>
<td>15449</td>
<td>3.2</td>
<td>3009</td>
<td>0.8</td>
<td>18458</td>
<td>2.1</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>सामाजिक आर्थिक सेवाएं</td>
<td>6279</td>
<td>1.3</td>
<td>8301</td>
<td>2.2</td>
<td>14580</td>
<td>1.7</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>सामाजिक सेवाएं</td>
<td>1393</td>
<td>0.3</td>
<td>811103</td>
<td>3.0</td>
<td>12496</td>
<td>1.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सामाजिक सेवाएं</td>
<td>72284</td>
<td>14.8</td>
<td>110989</td>
<td>30.0</td>
<td>183273</td>
<td>21.3</td>
<td>18.2</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल</td>
<td>489361</td>
<td>100.00</td>
<td>369839</td>
<td>100.00</td>
<td>859200</td>
<td>100.00</td>
<td>100.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

62. नौवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002) खण्ड 1 विकास तथा कार्यक्रम और नौवी भारत सरकार योजना आयोग नई विलिय पृष्ठ 195
मानक में राज्य-संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में आंकड़ों में अन्तर से बने रेल परिवर्तन हो सकते हैं क्योंकि बहुत से राज्यों द्वारा कार्यालय की सिफारिशों के आधार पर संशोधित आंकड़े भेजे जाने लेने हैं।

* इनमें विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता शामिल है। जो नीतियों पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के एक अंश के रूप में राज्यों को आवश्यक की जा रही है और इसलिए विशेष कार्यक्रमों के एक अंश के रूप में प्रतिबिंबित नहीं की जा रही है।

** कुछ राज्यों द्वारा जिनके सम्बन्ध में क्षेत्रीय ब्यौरा नहीं है। विकर्तरण के लिए विज्ञापन कार्य करने के कारण नीति योजना में राज्यों से सम्बन्धित आंकड़े अपवादस्वरूप अधिक हैं।

*** सूचना—प्रावधानिकी भी शामिल है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद की 49 वीं बैठक

राष्ट्रीय विकास परिषद की 49 वीं बैठक 1 सितंबर 2001 को विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में समाप्त हुई।

प्रथम गुरुदा जो विचारधृष्टि रखा वह था Draft approach paper to the tenth Five Year Plan. दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य संकल्प घोषित, उत्पाद का 8 प्रतिशत वार्षिक रहा गया सलाइड-2 से जानकारी मिलती है कि वृद्धि दर जो आजादी के तीन दशकों तक 3.5 प्रतिशत रही वहीं अगले दो दशकों 6 प्रतिशत के लगभग आ गयी।

63. नीती पंचवर्षीय योजना (1997-2002) खंड 1 विकास लक्ष्य कार्यनीति और नीतियों भारत सरकार के योजना आयोग नई दिल्ली पृष्ठ 212
(1) P.341- Dupty Chairman’s address at 49th NDC meeting on 1st September, 2001 at Vigyan Bhawan.

(2) P.- 341 Summary Record of discussion of NDC meeting Vol.-V (45th to 50th meeting) Govt. of India Planning Commission.

(3) प्रारूप पत्र में मानव विकास को गति देने वाले घटक आर्थिक सामाजिक तथा पर्यावरण से सम्बंधित है?

**Slide-3**

दसवीं पचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित उद्देश्य :-

1. प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर +8 प्रतिशत
2. निर्धारित लक्ष्य

- प्रत्येक गाँव को पेयजल उपलब्ध कराना।
Monitorable targets – Tenth Plan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Poverty Ratio</td>
<td>26%</td>
<td>21%</td>
<td>11%</td>
</tr>
<tr>
<td>Access to Primary Education</td>
<td>94%</td>
<td>100%</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Literacy Rate for 2001</td>
<td>65%</td>
<td>72%</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>Infant Mortality rate</td>
<td>72%</td>
<td>45%</td>
<td>28%</td>
</tr>
<tr>
<td>Maternal Mortality Rate*</td>
<td>4%</td>
<td>2%</td>
<td>.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Increase in forest/ tree cover</td>
<td>19%</td>
<td>25%</td>
<td>33%</td>
</tr>
<tr>
<td>Decadal population growth #</td>
<td>21.3</td>
<td></td>
<td>16.2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Per Thousand live birth

# For 1991-01 and 2001-11

(3) Slide-3 में एक सर्वचिह्नित विकास कार्यक्रम की स्थिरता बनायी गयी है जो समानता व सामाजिक न्याय के साथ सम्मिलित विकास में योगदान देगी। इस कार्यक्रम में कृषि विकास को सैद्धांतिक मूल्यांकन में रखा गया है।

(1) राज्य स्तरों पर अधिक तथा उन लक्ष्यों का निर्धारण जो क्षेत्रीय असमानता घटाते हैं।
(2) समानता तथा सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि विकास
(3) कृषि विकास मुख्य तत्त्व
(4) उन क्षेत्रों का तीव्र विकास जहाँ रोजगार की अवधि सम्मानवानाएं है।
(5) स्लाइड 6 में, विरोधयोग्य क्षेत्रों को दर्शाया गया है।
(1) 1990 के दशक में अनुपात क्षेत्रों में मिलाकर
(2) गरीबी रेखा 26 प्रतिशत तक किन्तु नन्दी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 18 प्रतिशत प्राप्त नहीं।

64. Employment growth to keep pace with addition to labour force.
65. Summary Record of Discussions of the N.D.C. meetings vol. V (45th to 50th Meetings) Govt. of India Planning Commission.
Slide-4, P-341
(3) निर्माण, शिक्षा मुद्रा दर, कुपोषण तथा लिंग असमानता जारी।
(4) वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत नवीं पंचवर्षीय योजना जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह 6.3 प्रतिशत थी।
(5) 90 के दशक में राज्यों में वृद्धि की असमानता।
(32) दूसरा मुद्रा जो इस विचार विभाग में मुख्य था वह है :-
राष्ट्रीय विकास परिषद की उस उपसमिति की रिपोर्ट पर वांछा जो बड़ी प्रामाणीय निर्धारण उन्मूलन कार्यवांशों के वित्त निर्धारण का दायरा तय करती है।68 यह उप समिति पिछली राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में गठित की गयी थी - इस समिति में यह निर्णय लिया गया है - 15 प्रतिशत हिस्सा योजना आयोग के द्वारा आये जोकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है तथा योजना आयोग एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनायेगा, जो उन मुद्रों पर नजर रखने वाली जिनका सुझाव राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है।67
(33) दूसरा मुद्रा राष्ट्रीय विकास परिषद की उपसमिति की केंद्र निर्धारित योजनाओं के हस्तांतरण का था- इस मुद्रे पर यह निर्णय लिया गया कि राज्य कोई भी ऐसा योजना इस उपसमिति को दे सकती है, जो इस मुद्रे से सम्बन्धित हो।
(34) उत्तराखंड की विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने का मुद्रा भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्बन्ध रखा गया।
(35) अंतिम मुद्रा नवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती समीक्षा का था।

10वीं पंचवर्षीय योजना
राष्ट्रीय विकास परिषद की 50वीं बैठक

50वीं राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक सकारात्मक व उज्ज्वल भव्यता योजना को आधार रखकर 21 जनवरी 2002 में प्रधानमंत्री श्री आटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में विज्ञापन भवन में शुरू की गई।
राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य (10वीं पंचवर्षीय योजना के लिये)68

1. आने वाले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना।

66. Summary Record of Discussion of NDC meeting Vol-V (48th to 50th meetings) Govt. of India Planning commission P-349.
67. Same P-348
68. Summary Record of Discussions of the National Development Council's 50th meeting Vol. V Govt. of India, Planning Commission-New Delhi P-446

144
2. सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8 प्रतिशत सालाना।
3. लाभ के लिये उन तरीकों को अपनाना।

स्लाइड—2— पिछले 2 दशकों में भारत, विश्व के 10 तीव्रतम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एक रहा है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को और प्रगति की ओर अग्रसर करना है, जिसकी सम्यकता मद्दत दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तय की गयी है।

स्लाइड—3— सितंबर 2001 की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया, वह केवल दसवीं पंचवर्षीय योजना को सकल बनाने के लिये नहीं था, बल्कि देश की प्रगति तथा विकास के सहायक होगा। इस प्रारूप में अन्य क्षेत्रों जैसे निर्माण, उन्नयन तथा रोजगार अवसरों को पैदा करना भी सम्मिलित था। जिनमे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो :-

- निर्माण की अनुपात में 5 प्रतिशत की कमी 2007 28 प्रतिशत से 21 प्रतिशत
- उछाली रोजगार क्षेत्रों में वृद्धि।
- 2003 तक प्रत्येक बच्चा स्कूल जाये तथा 2007 तक प्रत्येक बच्चा स्कूल में अपने पाँच वर्ष पूरे करे।
- साक्षरता एवं बेहतर भुगतान में 50 प्रतिशत तक लिंग विभेद साक्षरता करना।
- प्रत्येक ग्राम में पीने का पानी उपलब्ध करना।
- बढ़ी प्रदूषित नदियों की सफाई कार्यक्रमों का विस्तार

स्लाइड—590

इस स्लाइड में 50 मिलियन रोजगार अवसरों का जिक्र किया गया।

- दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 35 मिलियन लोगों को लेबर फोर्स से जोड़ा जायेगा।
- व्यापार में 8 प्रतिशत की वृद्धि 30 मिलियन रोजगार अवसरों को जन्म देगी।
- रोजगार इंटरनेशनल क्षेत्र तथा कार्यक्रम में 8 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से 50 मिलियन रोजगार अवसर पैदा होंगे।

69. Summary Record of Discussions of the National Development Council's 50th meeting Vol. V Govt. of India Planning Commission-New Delhi P-447

145
2. सकल परेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8 प्रतिशत सालाना।
3. लाभ के लिये उन तरीकों को अपनाना।

स्लाइड-2— पिछले 2 दशकों में भारत, विश्व के 10 तीनतम विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एक रहा है तथा दसवीं यंत्रवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को और प्रगति की ओर अग्रसर करना है, जिसकी समयावधि दसवीं पद्धतीन्य योजना के अन्त तक तय की गयी है।

स्लाइड-3— सितंबर 2001 की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में दसवीं यंत्रवर्षीय योजना के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया, वह केवल दसवीं यंत्रवर्षीय योजना को सकल बनाने के लिये नहीं था, बल्कि देश की प्रगति तथा विकास के सहायक होगा। इस प्रारूप में अन्य क्षेत्रों जैसे निर्यात, उद्योग तथा रोजगार अवसरों का पैदा करना भी समर्पित था। जिनमें जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो :-

- निर्माण अनुपात में 5 प्रतिशत की कमी 2007-26 प्रतिशत से 21 प्रतिशत
- लाभकारी रोजगार क्षेत्रों में वृद्धि।
- 2003 तक प्रत्येक बच्चा स्कूल जाये तथा 2007 तक प्रत्येक बच्चा स्कूल में अपने पौंच वर्ष पूरे करे।
- साक्षरता एवं वेतन भुगतान में 50 प्रतिशत तक लिंग विभेद खत्म करना।
- प्रत्येक गांव में थोपने का पानी उपलब्ध करना।
- बड़ी प्रूढ़ित नदियों की सफाई कार्यक्रमों का विस्तार

स्लाइड-5

इस स्लाइड में 50 मिलियन रोजगार अवसरों का विषय किया गया
- दसवीं यंत्रवर्षीय योजना के अन्तर्गत 35 मिलियन लोगों को लेबर फोर्स से जोड़ा जायेगा।
- व्यापार में 8 प्रतिशत की वृद्धि 30 मिलियन रोजगार अवसरों को जन्म देगी।
- रोजगार इन्टेन्सिव क्षेत्र तथा कार्यक्रम में 8 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से 50 मिलियन रोजगार अवसर पैदा होंगे।

69. Summary Record of Discussions of the National Development Council's 50th meeting Vol. V Govt. of India, Planning Commission-New Delhi P-447

145
पायेगी। यहाँ तक कि 8 प्रतिष्ठान की औसत वार्षिक विकास दर से भी, अर्थव्यवस्था द्वारा दसवीं योजना अवधि के दौरान तीन करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन की समाप्ति है जबकि इसी अवधि में करीब साढ़े तीन करोड़ लोक कार्यवाल से जुड़ते हैं। अतः ऐसी उपयुक्त कार्य नीतियाँ तैयार करना आवश्यक हो जाता है जो विकास प्रक्रिया में परिवर्तन द्वारा कार्यसृजन की गति को तीव्र कर सके।

योजना आयोग में इस विषय पर पर्याप्त कार्य किया गया है और यह महसूस किया गया है कि ऐसे अनेक क्षेत्र और आर्थिक कार्यकलाप हैं जिनमें संचालन के नीतिगत एवं कार्यक्रम समस्याओं का यादान से श्रम समाधान को उल्लेखनीय ढंग से बढ़ाने की क्षमता मौजूद है। जूल निजात यह कार्यनीति व्यक्तिगत उद्योगीला और स्व रोजगार को प्रोत्साहित करने पर निर्भर करती है तथापि यह विविध है कि इन कार्यकलापों के लिए अपेक्षित कौशल हमारी गौरूता72 शिक्षा और प्रशिक्षण पद्धति द्वारा पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं किये जाते। अतः विभिन्न प्रकार के कौशल की मांग और आवृत्ति के बीच सामान्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यवसायिक शिक्षा पर आवश्यक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

तीसरी विशेषता हमारा विश्वास है कि अभिशासन की गुणवत्ता में सुधार लाना सफलता के लिए अनिवार्य है प्रशासनिक और न्यायिक कुशलता एक स्वदेशी बाजार अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम का मूल केन्द्र है और कल्याणकारी योजनाओं की सफलता मुख्य रूप से सार्वजनिक कार्ययोजना व्यवस्था की कुशलता द्वारा निर्भर होती है। शेष योजना, खुशबू नियमित की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती। हमारे सभी सार्वजनिक संस्थाओं में और पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता लाना हमारे देश की क्षमता और टिकाको सामाजिक विकास को प्रसार करने की कुंजी है।73

अतः दसवीं पंचवीकरण योजना में, क्षेत्रीय निवेश, स्वीकार और योजनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त, जो कि हर पंचवीकरण योजना के अभिन्न अंग रहे हैं प्रलंबक खेत्र इतने केन्द्र एवं राज्यों के लिए अपेक्षित नीति के संरचनात्मक सुधारों का भी उल्लेख किया गया है। दूसरे शब्दों में पूर्ण सुधार एजेंडा जो योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक माना जाता है एक व्यापक अध्ययन में संशोधित रूप में दिया

72. प्रकाशन दसवीं पंचवीकरण योजना 2002–2007 खंड 1 आव्याम और कार्यनीतियाँ योजना आयोग
73. वही पृष्ठ सैंस–5
147
गया है तथापि यह महसूस किया गया है कि अपेक्षित प्रयासों की विसाहता ऐसी हो कि सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही के बारे में कोई असफलता न रहने पाए।

दसवीं योजना के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को देखते हुए अपनाए गये कार्यनीतिक दृष्टिकोण सम्बन्धी कुछ बातों का उल्लेख करना भी संगत होगा। 8 प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियंत्रण व्यवस्था व नियोजन दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि आवश्यक है, इसलिए संवेदनशीलता उस मात्रा में नहीं जितनी कि आमतौर पर मानी जाती है। विश्वविद्यालय के उपर्युक्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त अवतरित क्षमता है। इसलिए नियोजन योजना संसाधनों में किसी किसी अनुपातीक वृद्धि के आउटपुट अनुपात (आईसीआईआरो) में कभी अवैध चाहिए तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हम पूर्ण रूप से परम्परागत रहे हैं और दसवीं योजना के लिए आईसीआईआरो का जो अनुमान लगाया गया है वह आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपेक्षाकृत कम था।74

पारंपरिक रूप से प्रति व्यक्ति आय के स्तर को देख के आर्थिक उद्यान का एक सार्वजनिक संचालन सम्बन्ध गया है और इसलिए विकास के लक्ष्यों में प्रति व्यक्ति आय अथवा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पर बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में न केवल दसवीं योजना अवधि के लिए बल्कि अगले सभी दस वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरणाकार की परिकल्पना आधार रही है।

दूसरीकोण पत्र में प्रस्ताव किया गया था कि दसवीं योजना का उद्देश्य 2002-07 अवधि के लिए 8 प्रतिशत औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का एक संकेत लक्ष्य होना चाहिए। यह निश्चित ही एक बड़ा लक्ष्य है। विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि इस समय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 8 प्रतिशत से कम हो गयी है। यदि इस कमी को एक अल्पकालिक लक्षण के तौर पर देखा जा ए तो विगत अनेक वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण निर्धारण से पता चलता है कि प्रदर्शित क्षमता केवल लगभग 6.5 प्रतिशत है, इसलिए प्रस्तावित 8 प्रतिशत विकास लक्ष्य का अर्थ हाल ही के महत्वपूर्ण निर्धारण की तुलना में कम से कम 1.575 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि है जो काफी अधिक है।

फिर भी राष्ट्रीय विकास परिषद ने दसवीं योजना अवधि के लिए 8 प्रतिशत विकास लक्ष्य

74. प्राकृतिक दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 खण्ड 1 आधार और कार्यनीतियों योजना आयोग
75. यही पृष्ठ संख्या-5
अनुमोदित करके भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतानिहित क्षमताओं में अपना विकास प्रकट किया है।

दृष्टिकोण पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि आर्थिक वृद्धि ही राष्ट्रीय आयोजना का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है और वस्तुतः पिछले वर्षों के दौरान विकास उद्देश्यों की परिभाषा न केवल जी0.8 पर अथवा प्रतिवर्षीय आय में वृद्धि की दृष्टि से की जा रही है बल्कि मोटे तौर पर मानव कल्याण की संबंधित की दृष्टि से भी की गई है। विकास आयोजना में हेन आयामों के महत्व को परिलक्षित करने के लिए योजना में मानक विकास के कुछे प्रमुख संकेतों के साथ-साथ विशिष्ट तथा मानीत्स संकेत भी निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस बात का अनुभव किया है कि 8 प्रतिशत विकास लक्ष्य के अंतिरित निम्नलिखित लक्ष्यों को भी योजना के उद्देश्य प्राप्त करने का एक युद्धा समझ जाना चाहिए,--

1. 2007 तक 5 प्रतिशतांक बिन्दु तक और 2012 तक 15 प्रतिशतांक बिन्दु तक निर्धारित अनुपात को कम करना।
2. दसवीं योजना अवधि के दौरान श्रमिक बल में होने वाली वृद्धि के लिए वाला लाभप्रद और उच्च कोटि के रोजगार की व्यवस्था करना।
3. 2003 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा 2007 तक सभी बच्चों के लिए 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा।
4. 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में संग्रह अंतर में कम से कम 50 प्रतिशत तक की कमी।
5. 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर को 16.20 प्रतिशत तक की कमी करना।
6. योजना अवधि के अंतर साक्षरता दरों को 75 प्रतिशत तक बढ़ाना।
7. 2007 तक 45 प्रति हजार जीवित जन्मों तक और 2012 तक 28 प्रति हजार जीवित जन्मों तक शिशु मृत्यु दर (आई0 एमोआरो) में कटाई।
8. 2007 तक मातृ मृत्यु अनुपात (एम0 एम0 एआर0) में 2 प्रति हजार और 2012 तक एक प्रति हजार जीवित जन्मों की कमी।
9. 2007 तक 25 प्रतिशत तक और 2012 तक 33 प्रतिशत तक वन और वृक्ष क्षेत्र कवर में
वृद्धि।
(10) योजना अवधि में सभी ग्रामों को पेयजल की सतत रूप से सुलभता: सभी दृष्टि नदियों को 2007 तक तथा अन्य अधिसूचित दुर्गंधों को 2012 तक साफ करना।

ये लक्ष्य इस विषय को परिलक्षित करते हैं कि मात्र आर्थिक वृद्धि से दीर्घावधि संचारणीयता और सामाजिक न्याय में पर्याप्त सुधार प्राप्त नहीं किया जा सकता। पिछली योजनाओं में इनमें से अनेक मुद्रे उद्देश्यों के रूप में थे, अनुमानों के अनुसार, अनिवार्य नहीं हों किन्तु वकालत से होने होंगे। इस प्रकार इस अवधि सर्वोत्तम प्रयास। दृष्टिकोण के सामान्य रूप से अपनाया गया किन्तु दसवीं पंचवर्षिय योजना में इन लक्ष्यों को उतना ही महत्वपूर्ण समझा गया है जितना कि विकास लक्ष्य के रूप में योजना की रूपरेखा को।

दसवीं पंचवर्षिय योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अधिसूचित लक्ष्य कुल मिलाकर या तो प्रत्यक्ष लिंकेज के माध्यम से, जो मौजूदा अथवा संसाधनों के माध्यम से जो अवधि गहन सार्वजनिक हस्तक्षेपों के लिए विकास प्रक्रिया द्वारा सृजित होते हैं 8 प्रतिशत विकास लक्ष्य के संगत है। दृष्टिकोण पत्र के तौर पर कर्ता समय विवाद में देखी गई अर्थव्यवस्था बार समूहिक प्रृत्तियों के आधार पर इन लिंकेज का आकलन किया गया था और यह माहसूस किया गया था कि इन लक्ष्यों की उपलब्धि में भी समन्वित प्रयास की आवश्यकता होगी। बाद में योजना आयोग द्वारा किये गए व्यापक अध्ययनों और विश्लेषणों से पता चला है कि जहाँ तक रोजगार वृद्धि और गरीबी में कमी लाने का सम्बन्ध है, बेहतर उत्पादन और सुधार करना सम्भव है।

प्रति वर्ष 10 मिलियन रुपयों अवसरों का निर्धारण करने सम्बंधी विशेषज्ञ जो प्राधिकरण 78 विजय पर पर विवाद के लिए गठित किया गया था ने सूचित किया था कि उपयोग क्षेत्रीय धारा केन्द्रों और निदेशक हस्तक्षेपों से, केवल विकास प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों के बजाय पूर्वसे से अधिक रोजगार अवसर सृजन होंगे। जिससे न केवल श्रम बल में वृद्धि का धारा रखा जा सकेगा बल्कि इसलिए वर्तमान घाटा का बैठकण भी कम होगा। इसी प्रकार योजना आयोग में की गई आत्मनिर्भर प्रक्रियाओं ने सूचित किया कि समुदाय विकास लक्ष्य का राज्यवाद विश्लेषण, जो क्षेत्रीय असंतुलनों के

---
78. प्राधिकरण दसवीं पंचवर्षिय योजना 2002-2007 खंड 1 आयाम और कार्यनिर्देशों योजना आयोग पुष्त संख्या-6
समाधान की मांग करता है, से सामूहिक प्रभावितों के आधार पर किए गए आकलन के स्थान पर गरीबी दर में तेजी से कमी हो सकती है। अतः दसवीं योजना इन दो क्षेत्रों में लक्ष्यों की उपलब्धि की मांग करती है, जो दृष्टिकोण पत्र में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से भी पहले हैं।

उपर्युक्त अध्याय में हमने राष्ट्रीय विकास परिषद एवं विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तृत विवेचन किया है। पंचव अध्याय में नियोजन की राजनीतिक गत्यात्मकता का विस्तृत विवेचन किया जायेगा।

77. प्रकाशन दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007 खण्ड 1 आदाय और कार्यनीतियाँ योजना आयोग पुस्त संख्या--7 151